● वर्ष-3
● अंक-159
रायपुर, रविवार
11 फरवरी 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› सेम टू सेम माधुरी लगती है.....

पांच साल रिफॉर्म-परफॉम-ट्रांसफॉर्म के-मोदी

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये पांच वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रहे। यह बहुत कम होता है कि सुधार हों, काम हों और हम बदलाव को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखें। सत्रहवीं लोकसभा के माध्यम से आज देश अनुभव कर रहा है और मुझे भरोसा है कि देश सत्रहवीं लोकसभा को जरूरत आशीर्वाद देता रहेगा। अध्यक्ष जी, कभी-कभी सुमित्रा जी हास्य करती थीं, लेकिन आपका चेहरा हमेशा मुस्कराता हुआ रहता है। अनेक परिस्थितियों में आपने संतुलित भाव से इस सदन का मार्गदर्शन और नेतृत्व किया। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं।

आपने स्थाई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। आपकी पहल और सभी के संयुक्त प्रयास की वजह से 17वीं लोकसभा में 97त्न कामकाज हुआ है। यह अपने आप में प्रसन्नता का विषय है। सात सत्र तो सौ फीसदी से ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले रहे। अपने रात-रात भर बैठकर हर सांसद की बात को सरकार के ध्यान में रखने का प्रयास किया। मैं इस सफलता के लिए सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं।

आजादी के पल के लिए सेंगोल

संसद का नया भवन होना चाहिए, इसकी सभी ने चर्चा की। लेकिन ये आपका नेतृत्व है, जिसने इस काम को आगे बढ़ाया। उसी का परिणाम है कि आज देश को नया संसद भवन प्राप्त हुआ है। संसद के नए भवन में विरासत का अंश और आजादी के पहले पल को जीवंत रखने के लिए सेंगोल रखने का काम हुआ। यह भारत की आने वाली पीढ़ियों को हमेशा आजादी के प्रथम पल के साथ जोड़कर रखेगा। हमें इससे देश को आगे ले जाने की प्रेरणा भी मिलेगी।

नए सदन में भारत की मूलभूत मान्यताओं को आवाज

पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर के लिए हुए बड़े फैसलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, सरकार जम्मू-कश्मीर को सामाजिक न्याय का वादा देकर संतोष का अनुभव कर रही है। आतंकवाद नासूर बन कर देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता था। मां भारती की धरा आए दिन रक्तरंजित होती थी। देश के अनेक वीर, होनहार सपूत आतंकवाद की बलि चढ़ जाते थे। हम आंतकवाद के विरुद्ध थे। हमारे सदन ने आतंकवाद के खिलाफ कई कानून बनाए।

नारी शक्ति वंदन कानून

हाल ही में बदले गए आपराधिक कानूनों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हम 75 वर्षों तक अंग्रेजों की दी गई भारतीय दंड संहिता में ही जीते रहे। हम गर्व से कहेंगे, देश 75 साल दण्ड संहिता में जिया हो लेकिन आने वाली पीढ़ी न्याय संहिता में जिएगी। यही सच्चा लोकतंत्र हैं। नया सदन का प्रारंभ ऐसे काम से हुआ है जो भारत के मूलभूत मान्यताओं को बल देता है, वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण) है।

अंग्रेजों के कानूनों को बदला

बता दें कि केंद्र सरकार ने 125 साल से अधिक अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानून- भारतीय दंड संहिता , दंड प्रक्रिया संहिता और एविडेंस एक्ट को बदल दिया है। अब इन तीनों कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून अस्तित्व में हैं।

भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है

बकौल पीएम मोदी, आज मैं देख रहा हूं, बच्चों के मुंह से निकल रहा है कि अगले 25 साल में हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने कहा, 25 साल मेरे देश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण काल है। मुझे विश्वास है कि हम में से कोई नहीं होगा जो 25 साल में देश का विकास न कर सके। यह लोगों का संकल्प बन रहा है। इन पांच वर्ष में युवाओं के लिए बहुत कानून भी बने हैं। व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर युवाओं को कई मौके दिए गए। पेपर लीक जैसी समस्या युवाओं को चिंतित करती थी, हमने बहुत ही कठोर कानून बनाए हैं। युवाओं के मन में सवालिया निशान और व्यवस्था के प्रति उनका गुस्सा था। लेकिन हमने कानून बनाकर उन्हें दूर किया है।

प्रधानमंत्री ने अनुसंधान की अहमियत भी बताई

ये बात सही है कोई भी मानव जाति अनुसंधान के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। मानव जाति का लाखों साल का इतिहास रहा है, जीवन बढ़ता चला गया है, अनुसंधान चलता रहा है। सदन ने विधिवत रूप से कानून के जरिए अनुसंधान को बढ़ावा देने का काम किया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के जरिए उल्लेखनीय काम हो रहे हैं।

कौन बनेगा पीएम मोदी का उत्तराधिकारी?

आम चुनाव 2024 में कुछ ही महीने का वक्त शेष रह गया है। ऐसे में मूड ऑफ द नेशन ओपिनियन पोल में पीएम मोदी के लिए लगातार तीसरी बार कार्यकाल का अनुमान लगाया जा रहा है। मतदाताओं के मन में एक सवाल उठता है कि कौन सा भाजपा नेता पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार, 29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के लिए सबसे उपयुक्त पाया, जबकि 25 प्रतिशत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया।केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उनके पीछे रहे, सर्वेक्षण में शामिल 16 प्रतिशत लोगों ने नागपुर के सांसद का समर्थन किया। मूड ऑफ द नेशन का फरवरी 2024 संस्करण सभी लोकसभा सीटों पर 35,801 उत्तरदाताओं के सर्वेक्षण पर आधारित है। जनमत सर्वेक्षण गलत हो सकते हैं। मूड ऑफ द नेशन पोल 15 दिसंबर, 2023 और 28 जनवरी, 2024 के बीच आयोजित किया गया था।

जब मुख्यमंत्री ने मांदर की थाप में किया कर्मा नृत्य

मांदर की थाप, आकर्षक वेशभूषा और आदिवासी लोक नृर्तकों की लयबद्धता भला किसको आकर्षित नहीं करेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय भी अपने आप को नहीं रोक सके और अपने गृहग्राम बगिया में कर्मा दलों के आग्रह पर सपत्निक शामिल होकर नृत्य किया। एक मंझे लोक कलाकार की तरह नृत्य करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय को देखकर जनमानस को सुखद अनुभूति हो रही थी कि उनमें आदिवासी संस्कृति के प्रति वहीं आदर भाव और सम्मान है।

भाजपा के जय श्री राम के नारे नफरत- गुस्सा को दर्शाते हैं

कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने शनिवार को भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि उसके सदस्यों द्वारा जय श्री राम के नारे गुस्से और नफरत को दर्शाते हैं, और उनसे महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की पूजा करने की परंपरा को छोड़ने का आग्रह किया। ऐतिहासिक राम मंदिर के निर्माण और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर लोकसभा में बहस में भाग लेते हुए गोगोई ने कहा कि भगवान राम सबके हैं और हर समय सबके साथ हैं। वह हर क्षण हमारे कण-कण में है।

चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद जयंत एनडीए खेमे में पंहुचे! लेकिन सीटों पर बात यहीं अटकी

नई दिल्ली. राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के साथ भाजपा का गठबंधन शुक्रवार को तय लग रहा था और उनके प्रमुख जयंत चौधरी ने इसकी पुष्टि तब की जब मोदी सरकार ने अपने दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की। चौधरी ने कहा, मैं गठबंधन के लिए भाजपा को कैसे मना कर सकता हूं। कोई कसर रहती है (क्या कोई गुंजाइश बची है) उन्होंने आगे कहा कि किसी अन्य सरकार ने चरण सिंह के योगदान को स्वीकार नहीं किया। यह मोदी जी का दृष्टिकोण था... वह देश के मूल मूल्यों को समझते और जानते हैं।

आम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले चौधरी का भाजपा के साथ गठबंधन विपक्ष के भारतीय गुट को एक और झटका देगा। न केवल यह पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में मुश्किल स्थिति में है, बल्कि इसने अपने प्रमुख वास्तुकारों में से एक - जनता दल (यूनाइटेड) के नीतीश कुमार - को पिछले महीने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के हाथों खो दिया है।

इस बीच बीजेपी अलग-अलग राज्यों में अपना रुख मजबूत कर रही है. बिहार में नीतीश के अलावा, उसे महाराष्ट्र में विपक्षी दलों शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) से अलग हुए गुटों का समर्थन प्राप्त है। चौधरी की पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाताओं के बीच काफी समर्थन प्राप्त है। 2019 में भाजपा इस क्षेत्र की 27 सीटों में से आठ हार गई क्योंकि समाजवादी पार्टी (एसपी), बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) और आरएलडी ने हाथ मिलाया और जाट-मुस्लिम वोट को मजबूत किया। जबकि चौधरी ने एसपी के साथ सीट-बंटवारे का समझौता कर लिया था, पिछले हफ्ते से ऐसी अटकलें थीं कि वह पाला बदलने के लिए तैयार हैं। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि गठबंधन पर औपचारिक घोषणा एक-दो दिन में कर दी जाएगी। भाजपा अध्यक्ष मुजफ्फरनगर का दौरा कर रहे हैं। हो सकता है कि जयंत कार्यकर्ताओं के बीच संदेश भेजने के लिए उनके साथ जाएं। सूत्रों ने कहा कि आरएलडी ने इस सप्ताह केंद्रीय भाजपा नेताओं के साथ बातचीत की और दो मांगें रखीं- पहला, चरण सिंह के लिए भारत रत्न और लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए चार सीटें। समझा जाता है कि भाजपा ने रालोद को दो लोकसभा क्षेत्र और एक राज्यसभा सीट की पेशकश की है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि आरएलडी ने 2019 में तीन सीटों - मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर - पर चुनाव लड़ा था। एक दूसरे सूत्र ने कहा गठबंधन राजनीतिक रूप से दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और 2019 में एसपी-बीएसपी-आरएलडी गठबंधन के कारण पश्चिमी यूपी में बीजेपी को आठ सीटों का नुकसान हुआ।

सूत्र ने कहा भाजपा रालोद के साथ गठबंधन करके उस नुकसान की भरपाई करना चाहती है। चाहे 2002 हो या 2009, रालोद को भाजपा के साथ गठबंधन में हमेशा फायदा हुआ है।

प्रमुख समाचार

भाजपा को चुनावी बॉन्ड से लगभग 1300 करोड़ मिले

नयी दिल्ली। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 2022-23 में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से लगभग 1300 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। यह राशि इसी अवधि में इस माध्यम (चुनावी बॉन्ड) से विपक्षी दल कांग्रेस को प्राप्त धनराशि से सात गुना अधिक है। निर्वाचन आयोग को सौंपी गई पार्टी की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में भाजपा को कुल 2120 करोड़ रुपये मिले जिसमें से 61 प्रतिशत चुनावी बॉन्ड से प्राप्त हुए। वित्त वर्ष 2021-22 में पार्टी को कुल 1775 करोड़ रुपये का चंदा प्राप्त हुआ था। वर्ष 2022-23 में पार्टी की कुल आय 2360.8 करोड़ रुपये रही, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 1917 करोड़ रुपये थी। दूसरी ओर, कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड के जरिये 171 करोड़ रुपये की आय हुई, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 236 करोड़ रुपये से कम थी। भाजपा और कांग्रेस मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं। राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त पार्टी समाजवादी पार्टी (सपा) को 2021-22 में चुनावी बॉन्ड के जरिए 3.2 करोड़ रुपये की आय हुई थी। वर्ष 2022-23 में उसे इन बॉन्ड के जरिये कोई धनराशि नहीं मिली थी।

जयराम रमेश राज्यसभा में रहने के योग्य नहीं-जगदीप धनखड़

नयी दिल्ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के खिलाफ टिप्पणी के लिए जयराम रमेश की खिंचाई करते हुए कहा कि कांग्रेस सदस्य अपने कदाचार के लिए राज्यसभा में रहने के योग्य नहीं हैं। जयंत सिंह को उनके दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के मुद्दे पर सदन में बोलने की अनुमति देने के धनखड़ के फैसले पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक हुई। इस दौरान रमेश ने कुछ खास टिप्पणियां कीं। हालांकि हंगामे के कारण वह सुना नहीं जा सकीं। सभापति ने जयंत के खिलाफ टिप्पणी को लेकर रमेश को चेतावनी देते हुए कहा, ''मैंने सुना कि जयराम रमेश ने जयंत से क्या कहा... आप (रमेश) ऐसे व्यक्ति हैं जो श्मशान घाट पर उत्सव मना सकते हैं।'' धनखड़ ने कहा, ''यह तथ्य है कि आप (रमेश) इस दुर्व्यवहार के कारण इस सदन का हिस्सा बनने के लायक नहीं हैं।'' जयंत को सदन में बोलने का मौका दिए जाने का कांग्रेस सदस्यों ने जब विरोध किया तो धनखड़ ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ से बोलने की अनुमति दी।

महाराष्ट्र सरकार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए-उद्धव

मुंबई। शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार पर शनिवार को हमले तेज करते हुए उसे बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। ठाकरे ने दो दिन पहले मुंबई के दहिसर में उनकी पार्टी के नेता अभिषेक घोसालकर (40) की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना के मद्देनजर यह मांग की। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''हम महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। हम यह भी मांग करते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और नए सिरे से चुनाव कराए जाएं।'' पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर गुंडों को बचाने का भी आरोप लगाया। ठाकरे ने कहा, ''अगर पुलिस को खुली छूट दी जाए, तो वह 24 घंटे में सभी गुंडों को सलाखों के पीछे डाल सकती है, लेकिन गुंडों को सरकार का समर्थन प्राप्त है।'' उन्होंने घोसालकर की हत्या के तरीके पर भी सवाल उठाए।

भुट्टो-शरीफ की फिल्डिंग क्लीन बोल्ड हुए इमरान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव हुए हैं और दो दिन बाद भी पूरे नतीजे नहीं आ पाए हैं। ऐसी व्यवस्था से और क्या उम्मीद की जा सकती है। खबर लिखे जानें तक 265 में से 255 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। सबसे आगे इमरान खान के निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो अब तक 100 सीटें जीत चुके हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग है जिसके पास 73 सीटें हैं। बिलावल भुट्टो की पीपीपी को 54 सीटें मिली हैं। चौथे नंबर पर अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएमपी है, जिसके पास 17 सीटें हैं। नतीजों से साफ हो चुका है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है। ऐसे में सभी पार्टियां सरकार बनाने के लिए जोड़-तोड़ में लगी हैं। नवाज शरीफ की कोशिश है कि किसी भी हाल में सरकार वहीं बनाए, जबकि बिलावल चाहते हैं कि वो गद्दी पर बैठे।

संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन

अमीरात। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ ही दिन बाद पीएम मोदी मुस्लिम देश में भव्य मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी में पहला हिंदू मंदिर खुलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की दो दिवसीय यात्रा करेंगे, जिसके दौरान वह राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ व्यापक वार्ता करेंगे और अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शनिवार को यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि 2015 के बाद से यह प्रधान मंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की सातवीं यात्रा होगी। इसमें कहा गया है कि मोदी और अल नाहयान देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा, विस्तारित और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात करेंगे।

भारत रत्न : पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक... स्पष्ट हैं इसके राजनीतिक संदेश

गुलाम अहमद

भारत रत्न का सम्मान दिए जाने और न दिए जाने के पीछे हमेशा से राजनीति होती रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे नया अर्थ और प्रासंगिकता दी है। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख हों या फिर लालकृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर, यह उन लोगों को सम्मानित करने की मोदी की राजनीति के स्पष्ट संकेत थे, जिन्हें कांग्रेस द्वारा नजर अंदाज और तिरस्कृत किया गया था।

पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह के साथ कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने की मोदी की नवीनतम घोषणा से यह पता चलता है कि उनकी सरकार भारत की समकालीन राजनीति और अर्थव्यवस्था में इन तीनों हस्तियों की भूमिका को कितना महत्व देती है। इन्हें क्रमश- पहली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों, किसानों के हितों की वकालत करने वाले और बेहतर खाद्य उत्पादकता और सुरक्षा के लिए विज्ञान का उपयोग करने वाले चैंपियन के रूप में देखा जाता है। दिलचस्प यह है कि ये सभी 2024 के चुनावों के लिए नरेंद्र मोदी के अभियान के पसंदीदा विषय हैं।

दरअसल, महान कृषि

वैज्ञानिक डॉ. एमएस स्वामीनाथन को यह पुरस्कार 1960 के दशक में भारत के खाद्य संकट को खत्म करने के लिए हरित क्रांति को लाने में उनकी बड़ी भूमिका को मान्यता देता है। यह स्वामीनाथन की रणनीति ही थी, जिसकी बदौलत भारत के कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के सहयोग से बतौर वैज्ञानिक उनके काम के परिणामस्वरूप पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को उच्च उपज की किस्म वाले बीज, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और उर्वरक उपलब्ध कराए गए।

वर्षों बाद, 2004 से 2006 के बीच राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉ. स्वामीनाथन ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), जिस पर किसान अपनी फसलें सरकार को बेचते हैं, वह औसत उत्पादन लागत से कम से कम 50 फीसदी ज्यादा होना चाहिए। डॉ. स्वामीनाथन के योगदान का महत्व इस तथ्य से समझा जा सकता है कि आज ऐसा कोई दिन नहीं बीतता, जब किसानों के संघ कानूनी गारंटी के रूप में सभी उपज के लिए एमएसपी निर्धारित करने के लिए स्वामीनाथन फॉर्मूले को लागू करने की मांग न करते हों। यह महज संयोग तो नहीं हो सकता कि स्वामीनाथन को पुरस्कार तब दिया गया है, जब उपज की खरीद के लिए कानूनी गारंटी और बिजली के बिलों में संशोधन सहित अपनी लंबित मांगों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों द्वारा अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया गया हो। दूसरी तरफ, चुनावी वर्ष में नरसिम्हा राव और चरण सिंह को भारत रत्न पुरस्कार महज उनके योगदान को मान्यता नहीं है, बल्कि यह मतदाताओं की याद्दाश्त को ताजा करने का मोदी का तरीका है कि कैसे उन्होंने नेहरू-गांधी परिवार को चुनौती दी थी, जिससे सोनिया और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के बारे में भाजपा का जो नैरेटिव रहा है, उसे ही मजबूती मिलती है।

इससे पहले वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। आडवाणी भाजपा के राम मंदिर आंदोलन का चेहरा थे, जिन्होंने 1992 के उन दृश्यों को देखा था, जब भीड़ द्वारा विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। कालांतर में इस आंदोलन ने एक लंबी कानूनी लड़ाई का रूप लिया, जिसकी परिणति सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के रूप में हुई, जिसने भव्य मंदिर खोलने का मार्ग प्रशस्त किया। कर्पूरी ठाकुर की भूमिका तो और भी महत्वपूर्ण है। वह सिर्फ ओबीसी राजनीति का चेहरा नहीं थे, बल्कि कांग्रेस के कट्टर आलोचक और बिहार में कांग्रेस विरोधी आंदोलन का गढ़ भी थे।

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे 124 पटवारी

■ राजस्व कार्य ठप्प, किसानों के रकबे बढ़ाने का मामला

बलरामपुर रामानुजगंज। बलरामपुर जिले की नौ तहसील 200 हल्कों के 124 पटवारी किसानों के रकबे में अवैधानिक रूप से अन्य व्यक्तियों के रकबे में नाम जोड़ने को लेकर 12 पटवारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की अनुशंसा के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जिला मुख्यालय में बैठ गए हैं। इससे पूरे जिले का राजस्व कार्य ठप्प हो गया है। मामले में सरगुजा संभाग के कमिश्नर के द्वारा प्रभारी तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। पटवारी संघ के द्वारा जांच पर भी सवाल खड़ा करते हुए जांच अधिकारी शशि कुमार चौधरी के अन्यत्र किसी अन्य जिले में स्थानांतरण की भी मांग की है।

जिला पटवारी संघ के पदाधिकारीश धीरेंद्र उर्मलिया, चंचल कुमार मिरी, खिलंती नायक, शैलेष मेहता, हामिद रजा, विनय पांडेय, विमलेश सिंह, विशाल अग्रवाल, कृष्ण कुमार सिंह, नसीम उल हक, धर्मपाल सिंह, आनंद पांडेय, पवन पांडेय, ऋचा यादव, रमेश यादव, संजय सोनी, विजय यादव, अंकित गुप्ता, देवेंद्र विश्वकर्मा, करुणा नाग, साधना सिंह, नियति टोप्पो ने कहा कि गिरदावरी का कार्य 30 सितंबर तक हम लोग के द्वारा किया जाता है।

वहीं, 20 अक्तूबर तक संशोधन होता है। किसानों का पंजीयन समिति एवं तहसीलदार के

द्वारा किया जाता है। 30 अक्तूबर तक किसानों का पंजीयन हुआ। वहीं, संशोधन का अधिकार तहसीलदार के पास है। तहसीलदार के मॉड्यूल से संशोधन की कार्यवाही हुई तो इसमें पटवारी दोषी कैसे हैं। जब तहसीलदार के द्वारा संशोधन किया गया तो तहसीलदार के संशोधन की जांच हम नहीं कर सकते हैं, फिर हम लोगों के खिलाफ कार्यवाही की अनुशंसा क्यों की गई।

शशि चौधरी के तबादले की मांग

पटवारी संघ ने कहा कि जिले में विवादित रहे डिप्टी कलेक्टर शशि चौधरी के द्वारा अनावश्यक रूप से पटवारी को प्रताड़ित करने के लिए ऐसा कृत किया गया है। पूर्व में भी उनके द्वारा पटवारियों को प्रताड़ित किया गया था। यहां तक की जहां भी रहे हमेशा विवादित रहे। पटवारी संघ ने एक स्वर में शशि चौधरी के जिले से अन्य स्थानांतरण की मांग की है।

जिला खाद्य अधिकारी की भूमिका की हो जांच

पटवारी संघ ने कहा कि तहसीलदार के मॉड्यूल से जब कोई भी संशोधन होता है तो इसकी जानकारी जिला खाद्य अधिकारी के खाद्य मॉड्यूल में तत्काल प्राप्त होती है। रकबे में अप्रत्याशित वृद्धि की जानकारी खाद्य विभाग को होती है न की पटवारी को। ऐसे में जब उनके द्वारा रकबा संशोधन किया जा रहा था तो जिला खाद्य अधिकारी के द्वारा मौन क्यों धारण किया गया। जिला खाद्य अधिकारी की भूमिका की जांच हो एवं उनके खिलाफ कार्रवाई हो।

पटवारी ने नोटिस के बाद दिया जवाब

पटवारी संघ ने आरोप लगाया कि जांच त्रुटि पूर्ण हुई है। पटवारी ने नोटिस के बाद जवाब दिया। उनके खिलाफ कार्यवाही की अनुशंसा हुई। वहीं, जिस पटवारी ने जवाब नहीं दिया उनके खिलाफ कार्रवाई के अनुशंसा नहीं हुई। जिन संदिग्ध किसानों की सूची बनाई गई, उसमें कई किसानों के पास वैध दस्तावेज हैं। कई किसानों ने धान बिक्री ही नहीं की है, उनका भी नाम सूची में जोड़कर इस गंभीर मुद्दे की जांच को विवादित बनाने का काम जांच समिति द्वारा किया गया है।

अस्पताल प्रबंधन ने किया निरीक्षण फायर फाइटिंग सिस्टम मिला बंद

■ कर्मचारी बोले- चलाना ही नहीं आता

कोरबा। कोरबा जिला अस्पताल में मौजूद कैंटीन की व्यवस्था काफी खराब हो चुकी है। संचालक की लापरवाही का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले दिनों जब प्रशासन की टीम ने यहां का निरिक्षण किया था, तब काफी गंदगी पाई गई थी। इसके बाद उसे काफी फटकार लगाई गई थी और शोकाज नोटिस भी जारी किया था। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने भी यहां का निरिक्षण किया, जहां फायर फाइटिंग सिस्टम बंद मिला। प्रबंधन ने तत्काल फायर फाइटिंग मशीन की व्यवस्था की और संचालक को कैंटीन व्यवस्थित करने के निर्देश दिए।

कोरबा के मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल के कैंटीन को व्यवस्थित करने का प्रयास शुरु कर दिया है। अस्पताल प्रबंधन इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। पिछले दिनों प्रशासन की टीम ने कैंटीन का निरिक्षण किया था, जहां काफी गंदगी पाई गई थी। इतना ही नहीं सब्जियां भी खराब मिलीं, जिसके बाद अधिकारियों ने संचालक को जमकर

फटकार लगाई और शोकाज नोटिस जारी किया।

मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल के सह अधीक्षक डॉ. विकांत जाटवर ने बताया कि लापरवाही कैंटीन संचालक की है, जब फायर सेफ्टी लगाया गया है तो जवाबदारी बनती है कि कर्मचारियों को चलाना आना चाहिए। इसके अलावा उसमें गैस है कि नहीं इसकी भी समय-समय पर जानकारी लेनी चाहिए। उन्हें फोन कर जानकारी दी गई है। समय रहते सुधार दिया जाएगा।

कैंटीन में फायर फाइटिंग सिस्टम की व्यवस्था तो कर दी गई है। वहां काम करने वाली सरोजनी ने बताया कि मशीन का उपयोग करना आता ही नहीं है। जबकि किचन कितना संवेदनशील होता है इसकी जानकारी आपको भी होगी कि वहां गैस सिलेंडर होते हैं। जहां दुर्घटना होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। कर्मचारियों ने भी प्रबंधन को ट्रेनिंग देने की बात कही है, ताकी दुर्घटना होने पर वो स्थिती को संभाल सके।

अस्पताल के कैंटीन जैसे संवेदनशील स्थान का व्यवस्थित होना बेहद जरुरी है, ताकी मरीजों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बहरहाल व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास शुरु कर दिया गया है। आगामी कुछ समय तक पूरी व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी।

ओमान में बंधक दीपिका की हुई वतन वापसी, साय सरकार ने कराया रेस्क्यू

भिलाई। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों से भिलाई की रहने वाली जोगी दीपिका जोगी की वतन वापसी हो गई है। रोजगार की तलाश में दीपिका ओमान पहुंची थी और जहां उसे बंधक बना लिया गया था। अब प्रदेश सरकार महिला को बंधन मुक्त कराकर भिलाई ले आई है। दीपिका एंबेसी के सहयोग से शुक्रवार रात रायपुर एयरपोर्ट पहुंची। उन्हें लेने वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन खुद पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद दीपिका से उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और विधायक रिकेश सेन ने मुलाकात की।

दीपिका ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन का आभार जताया। उसने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से भारत वापस आई हूं, वरना कभी भारत वापस नहीं पाती। दीपिका ने बताया कि वहां एंबेसी में एक-एक साल से लोग वेटिंग में हैं। वहीं दीपिका ने बताया कि जिस घर में वह काम करना गई थी, वहां एक बूढ़ी महिला की सेवा करने के नाम पर लेकर गए थे। लेकिन उस बूढ़ी महिला के नौ बेटे थे और सभी बेटे के तीन से चार बच्चे थे। उस घर

में परिवार के 40 सदस्य थे और उस घर में वह अकेली काम करने वाली महिला थी। साथ ही अन्य काम भी कराया जाता था और नहीं करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी।

दीपिका जोगी ने सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले वीडियो पोस्ट कर मदद को गुहार गई थी। वीडियो में महिला ने बताया था कि उसे झूठ बोलकर ओमान में लाया गया और बंधक बना लिया गया। उसके साथ मारपीट की जाती है, वह वापस भारत नहीं लौट पा रही है। उसे दूसरे लोगो के पास बेचने की धमकी दी जा रही है। दीपिका ने बताया कि जब वो ओमान से निकली, तो उसके पास पैसे नहीं थे। इससे उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ शासन ने ओमान से दिल्ली और विधायक रिकेश सेन ने उसे दिल्ली से रायपुर लाने की व्यवस्था करवाई है।

हाउस मेड की नौकरी के लिए दीपिका केरल की एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से गई थी। खुर्सीपार निवासी मुल्ला मोहम्मद इमरान खान, हैदराबाद निवासी अब्दुल ने खाना बनाने का काम दिलाने की बात कही थी। इसके बाद दीपिका को दुर्ग से हैदराबाद ले जाया गया और फिर वहां से उसे मस्कट के लिए भेजा गया। मस्कट एयरपोर्ट से दीपिका को हफीजा के घर जैनब लेकर गई। जहां उसे बंधक बना लिया गया था।

सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार, सब इंजीनियर पर लगाया आरोप

कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर बैठे जनप्रतिनिधि

बालोद। बालोद जिले के आदिवासी विकासखंड डोंडी के अडजाल गांव से गुजरा पहुंच मार्ग के सड़क उन्नयन कार्य मे बरती जा रही लापरवाही को लेकर ग्रामीणों के साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष मिथलेश निरोटी, जनपद सदस्य ने निर्माणाधीन सड़क पर बैठकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने गुणवत्ता युक्त सड़क बनाने की मांग शासन प्रशासन से की है। वहीं, आदिवासी जनप्रतिनिधि ने लोक निर्माण विभाग के सब इंजीनियर पर उपेक्षा का आरोप लगाया है।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की देखरेख में चल रही उक्त सड़क उन्नयन कार्य में गुणवत्ताहीन कार्य होने की शिकायत जनप्रतिनिधियों ने दूरभाष पर लोक निर्माण विभाग बालोद के अधिकारियों से की तो लोक निर्माण विभाग के अनुविभागीय अधिकारी, सब इंजीनियर सड़क ठेकेदार के साथ पहुंचे। जनप्रतिनिधियों द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क निर्माण में

बरती जा रही लापरवाही को दिखा रहे थे। अधिकारियों ने मामला को शांत कराया व जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सड़क गुणवत्ता युक्त बनेगी।

लगभग आठ साल पहले लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त सड़क का निर्माण कराया गया था, किंतु तदसमय सड़क निर्माण के कुछ दिनों बाद डामर की परत उखड़ने लगी थी। जगह-जगह डब्लूएमएम की गिट्टियां उखड़कर बाहर आ गयी थी व अनगिनत गड्ढे सड़क में हो गये थे। ग्रामीणों के द्वारा पिछले तीन-चार सालों से उक्त सड़क का संधारण किये जाने की मांग शासन प्रशासन से कर रहे थे।

अब सड़क उन्नयन कार्य प्रारंभ हुआ तो मिट्टी की अच्छे से सफाई किये बिना डामर बिछाया जा रहा है। जगह-जगह बिछायी गयी डामर उखड़ रहा है। लगभग दो किलोमीटर की उक्त सड़क में बिछायी गयी। डामर में कहीं-कहीं तो सड़क के किनारे पतली डामर बिछाया गया तो कहीं-कहीं पर बीच में डामर ही नहीं लगा है। मिट्टी व पूर्व की गिट्टी दिख रही है।

गुजरा से अडजाल तक उक्त सड़क के उन्नयन कार्य की स्वीकृत राशि, निर्माण एजेंसी, कार्य प्रारंभ करने व पूर्ण होने की संभावित तिथि सहित अन्य जानकारी का सूचना पटल भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने लगवाना उचित नहीं समझा।

पूरे मामले में मिथलेश निरोटी उपाध्यक्ष जिला पंचायत बालोद ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत पर निर्माणाधीन सड़क को देखने पर ही लग रहा था कि कार्य शासन के मापदंड के अनुरूप नहीं बन रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गुणवत्ता युक्त सड़क बनाने का निर्देश देने की बात कही। वहीं, राजेश चुरेंद्र जनपद सदस्य गुजरा ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के सब इंजीनियर से उक्त सड़क निर्माण कार्य के संबंध में पूछने पर सही जानकारी न देते हुए ऑफिस में लेने की व जो करना है कर लो का जवाब दिया। एसनाथ अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग ने बताया कि उक्त सड़क उन्नयन कार्य में उक्त सड़क में अभी एलबीएम किया गया है। इसके बाद ओजीपीसी 20 एमएम किया जाएगा। इसके बाद 6 एमएम सिलकोट किया जाएगा। सड़क गुणवत्ता पूर्ण बनाने की बात कही।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

स्थाई वारंटी, हत्या, विस्फोट व फायरिंग की वारदात में शामिल 2 नक्सली गिरफ्तार

बीजापुर। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत डीआरजी व जांगला थाना की संयुक्त टीम बड़ेतुंगाली पोटेनार की ओर निकली थी, तभी पोटेनार के जंगल पगडंडी रास्ते मे एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर जंगल मे छिपने का प्रयास कर रहा था। घेराबंदी कर पुलिस ने विस्फोटक के साथ एक नक्सली कमलू सोढी को गिरफ्तार किया है। वहीं हत्या, विस्फोट व फायरिंग की वारदात में शामिल रहा वर्षों से फरार एक नक्सली मिलिशिया सदस्य सोढ़ी सन्नू को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के विरूद्ध 6 स्थाई वारंट भी लंबित है। उनके कब्जे से एक टिफिन बम, कॉर्डेक्स वायर, डेटोनेटर, नक्सल संगठन का पर्चा-बैनर और इलेक्ट्रिक वायर बरामद किया गया है।

सरपंच द्वारा अतिक्रमण किये भूमि को कराया गया मुक्त

नारायणपुर। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम करलखा में सरपंच अधारीराम सलाम ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करते हुए व्यावसायिक परिसर सहित बाउंड्रीवाल का निर्माण कर दिया था। इस अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार और वन विभाग को शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद तहसीलदार सहित वन विभाग के अधिकारियों ने करलखा गांव में पहुंचकर सरपंच द्वारा किए गए अवैध कब्जे का नापजोख किया था। इस नापजोख के बाद तहसीलदार ने नोटिस जारी कर सरपंच को शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी। इस चेतावनी के बाद भी सरपंच अवैध कब्जे को हटाने में रुचि नहीं दिखाई। जिसके बाद तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ करलखा गांव पहुंचकर सरपंच द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की। इसमें तहसीलदार ने व्यावसायिक परिसर सहित बाउंड्रीवाल पर बुलडोजर चलाते हुए अवैध कब्जे को धराशाई कर दिया। इस तरह तहसीलदार ने करीब 27 डिसमिल भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है।

कलेक्टर ने बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलायी

बेमेतरा। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने शनिवार को ज़िला स्तरीय शुभारम्भ कार्यक्रम में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर बच्चों को कृमिनाशक दवा (एल्बेंडाजोल) का सेवन कराया। कार्यक्रम का आयोजन ज़िला मुख्यालय स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल में आयोजित हुआ। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संतराम चुरेन्द्र, अनुविभागीय एवं दंडाधिकारी श्रीं युगल किशोर उर्वशा, ज़िला शिक्षा अधिकारी अरविंद्र मिश्रा, ज़िला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) श्रीमती लता सहित स्वास्थ्य विभाग,स्कूल प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षिका और छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने कहा कि बच्चों को अच्छी स्वच्छता की आदतें सिखाना महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने नाखून काटने और उन्हें साफ रखने के लिए कहना चाहिए।लंबे नाखून अक्सर विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के लिए आश्रय स्थल के रूप में कार्य करते हैं जो संक्रामक रोगों का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी बीमारी की आधे से ज्याया जड़ साफ़-सफ़ाई से ना रहना है।

पुलिस ने गुण्डाधूर की स्मृति में मनाया भूमकाल दिवस

सुकमा। जिला मुख्यालय में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सुकमा पुलिस ने आदिवासी क्रांतिकारी नेता व महानायक अमर शहीद गुण्डाधूर के संघर्ष की स्मृति में भूमकाल दिवस की 114 वीं वर्षगांठ मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर जिलें में नक्सलियों द्वारा हत्या किये गये ग्रामीणों का नाम स्मरण कर संवेदना व्यक्त कर मौन धारण किया गया। इस दौरान जिले के एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि गुंडाधुर को नमन करते हुए शनिवार को हम भूमकाल दिवस मना रहे हैं। नक्सलियों की विचारधारा खोखली है। ऐसी कोई विचारधारा नहीं है जिसमें निर्दोष ग्रामीणों को मारा जाए लेकिन नक्सली छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वर्ष 2000 से लेकर अब तक सिर्फ सुकमा जिले में ही 354 ग्रामीणों हत्या कर चुके हैं, इससे जिले का विकास रूक गया है। उन्होने नक्सलियों से हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने की अपील की है। इस कार्यक्रम के दौरान जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी किरण चव्हाण, पुलिस अधीक्षक, श्रीमती पारूल खण्डेलवाल आदि उपस्थित रहे।

सार्वजनिक जगह पर शराब पीना पड़ेगा महंगा

कबीरधाम। कबीरधाम जिले में अब सार्वजनिक स्थान पर बैठ कर शराब पीना व देर रात तक घूमना महंगा पड़ेगा। क्योंकि पुलिस द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार देर रात को जिले पंडरिया, कवर्धा, पांडातराई समेत कई थाना क्षेत्र में पुलिस ने आउटर एरिया में सार्वजनिक स्थान पर बैठ कर शराब पीने वालों की जमकर क्लास लगा रही है। इस दौरान पुलिस ने शराब प्रेमियों से उठक बैठक भी कराई है। साथ ही शराब पीने वाले लोगों से कचरे को साफ सफाई कराई गई। इसके अलावा कवर्धा शहर के आउटर में एरिया में देर रात तक घूमने वाले की एसपी ने क्लास ली। कबीरधाम एसपी डाक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि शहर के सुनसान जगह पर नवयुवक युवती, छात्र व छात्राएं प्रेमी जोडे बैठे रहते हैं। जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अक्सर आपराधिक घटनाएं सुने स्थान पर ही घटित होती हैं। नशेड़ी/ आपराधिक तत्व भी इन जगह पर घूमते रहते हैं। इस कारण पुलिस ने इन जगहों पर दबिश देकर क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने का बिडा उठाया है।

अवैध प्लॉटिंग करने वाले 146 भू स्वामियों को नोटिस

■ बिलासपुर के आसपास दर्जनों गांवों के भूमि स्वामी शामिल

बिलासपुर। अवैध प्लॉटिंग के सिलसिले में तखतपुर अनुविभाग के 14 गावों के 146 भू स्वामियों को नोटिस जारी की गई है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर एसडीएम तखतपुर श्री वैभव क्षेत्रज्ञ ने नोटिस जारी की है। उन्हें 9 तारीख को शाम 5 बजे तक वैध कागजात प्रस्तुत करने की मोहलत दी गई थी। जवाब प्रस्तुत नहीं करने वालों के प्लॉट पर बुलडोजर की कार्रवाई की जायेगी। सभी भूस्वामी बिलासपुर शहर के आसपास के रहने वाले गावों से हैं। उनके द्वारा भूमि की अवैध प्लॉटिंग कर छोटे छोटे टुकड़ों में भूखण्ड बेची जा रही है। न तो उन्होंने कॉलोनाइजर लाइसेंस लिया है और न ही नगर निवेश विभाग से नक्शा पास कराया है।

अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय तखतपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन 146 भू स्वामियों और अवैध प्लॉट काटने वालों को नोटिस जारी की गई है, उनमें उसलापुर के 3, नीरतु के 1, घुरू के 17, सैदा के 15, अमेरी के 13, पेंडारी के 17, समलपुरी के 3, सकरी के 9, छतौना के 9,भरनी के 8, मेंड्रा के 29, लोखंडी के 9, हांफा के 11 तथा जोकी के 2 लोग शामिल हैं। कुछ अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खुद के नाम पर भूमि है जबकि कुछ लोग भूमि स्वामियों से अवैध रूप से एग्रीमेंट लिखाकर भूमि पर प्लॉटिंग करवा रहे हैं।

सकरी तहसील के अंतर्गत ग्राम अमेरी, लोखंडी, विंध्यासेर,नीरतू, काठाकोनी के अवैध प्लॉटर जिन्हें नोटिस जारी की गई है, उनमें विनोद माधवानी, लवकुमार सिंह सरकंडा, ममता पाण्डेय अंबिकापुर, गणेश राम, बजरंग लाल, संतकुमार गुप्ता अमेरी, राधेश्याम साहू, तिलकनगर, सुजीत सिंह, विजय नथानी, नीलिमा जॉन अमेरी, रमनदीप सलूजा, जेठानंद ला, सिंधी कॉलोनी, पुष्पा पिता रामेश्वर, शत्रुघ्न पिता तिहारू, बिनबाई लोखंडी, उदय खांडे, छतलाल तिहारु लोखंडी, सतबतीं बाई, बाजहीन पिता तिहारू, संतकुमार पिता तिहारी, पांचों बाई पति तिहारू, सतबाई पिता तिहरू और जुबैर कुरैशी तारबहार को नोटिस जारी की गई है। सकरी तहसील के ग्राम भरनी में अश्विनी कुमार वगैरह, मनोज, यश रेलवानी, गुलशन पेसवानी, गोपाल मानिकपुरी, निर्मल दास, गौरव पिता रमेश कुमार को नोटिस। मेंड्रा के मेरान बक्शी, इंतजार, नूर मोहम्मद, गरीब दास मानिकपुरी, कलीम खान, प्रदीप पटेल, नंदलाल यादव लालाराम कर्ष, भास्कर निर्मल, खेदूराम, कनकराम, सुकुमार यादव, दुर्गा, अभिषेक दुबे, नागेश्वर शुक्ला, गणेश रजक, राहुल अग्रवाल, रमा बाई, सेवकराम साहू, संतोष भारद्वाज, उमेश प्रताप, अंजु सिंह, गौकरण, प्रमिल कुमार, संदीप कुमार अग्रवाल, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, जानकी अग्रवाल, कृष्ण कुमार, एनोश प्रकाश, चम्पा बाई, संजय कुमार , हरप्रसाद, सुवासिन बाई, सतीश कौशिक, रिद्धि सिद्धि मैनेजमेंट को नोटिस दिया गया है। छतौना से विनोद मिश्रा, रिद्धि सिद्धि मैनेजमेंट डायरेक्टर खुशबू पति विजय अग्रवाल, मनीषा बजाज, मायादेवी, हितेश, मनमोहन सिंह, मनीषा अग्रवाल, इंदु इंटरप्राइजेज शैलेश अग्रवाल, नूर मोहम्मद को नोटिस जारी की गई है। ग्राम सैदा के रविन्द्र पाटनवार, मो अमजद खान, दीपक अग्रवाल, हेमंत छितरका, दीपक साहू, प्रकाश कलवानी, अल्फा प्रॉपर्टीज संचालक मिथुन साहू, प्रदीप साहू, हरीश अग्रवाल, मुकेश कुमार आदि को नोटिस जारी किया गया है।

कांग्रेस के नेता सोमेन मंडल के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर

कांकेर। पंखाजुर प्रशासन ने कांग्रेस नेता सोमेन मंडल के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। वहीं, रीपन सदियाल और सुमित मांझी के घर प्रशासन ने बुलडोजर से ढहाया है। बताया जा रहा है कि ये सभी भाजपा नेता असीम राय हत्याकांड में आरोपी थे। अन्य आरोपियों के घर भी बुलडोजर चलने की संभावना है। राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन ने की संयुक्त टीम ने शनिवार सुबह इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।

बता दें कि भाजपा नेता असीम राय हत्याकांड में सोमेन मंडल भी आरोपी है। खुलासा होने के बाद सोमेन मंडल के अवैध कब्जा की शिकायत कर ढहाने की मांग की गई थी। शिकायत की जांच के बाद अवैध कब्जा ढहाने की कार्रवाई प्रशासन ने की है। सोमेन मंडल इस अवैध कब्जे पर मेडिकल दुकान संचालित करता था। गौरतलब है कि सात जनवरी देर रात को भाजपा नेता असीम राय को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद एसआईटी गठित टीम ने तेरह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हत्या की साजिश में सोमेन मंडल भी शामिल है। सोमेन ने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पैसे का लेनदेन किया था। इसके बाद से सोमेन के अवैध कब्जे को लेकर लगातार शिकायत की जा रही थी।

इसके पहले असीम हत्याकांड में शामिल पार्षद विकास पाल के अवैध कब्जे पर 22 जनवरी को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ढहाया था। अब प्रशासन ने दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमेन मंडल के अवैध कब्जा को ढहा दिया है।

असली अभिनंदन के हकदार आप सभी हैं : साय

■ टांगरगांव में अंशकालीन सफाई कर्मचारी कल्याण संघ अभिनंदन से अभिभूत हुए मुख्यमंत्री साय

जशपुर। असली अभिनंदन के हकदार आप लोग हैं, आपने हम पर जो विश्वास जताया जिसके कारण सत्ता में हमारी वापसी हुई। जो भी वादे किये हैं उस पर हम खरे उतरेंगे बस थोड़ी सी मोहलत चाहिये। ये विचार जिले के टांगरगांव में अंशकालीन सफाई कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए व्यक्त किये।

इससे पूर्व जशपुर के टांगरगांव में आयोजित अंशकालीन सफाई कर्मचारी कल्याण संघ अभिनंदन सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का लोगों ने ढोल बाजे एवं पारंपरिक करमा नृत्य से कियाभव्य स्वागत किया। जशपुर जिले के कांसाबेल के टांगरगांव मिनी स्टेडियम में आयोजित स्वागत और अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री का सम्मान करने के लिए यहां बड़ी संख्या में स्कूल कर्मचारी संघ, सफाई कर्मचारी संघ, लघु वनोपज सहकारी संघ, आंगनबाड़ी सहायिका संघ, रसोईया संघ, और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने माँ सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित कर समारोह की शुरुआत की।अभिनंदन समारोह में जशपुरिया परम्परा के अनुसार मुख्यमंत्री का पांव धोकर एवं पगड़ी पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विष्णुदेव साय ने कहा कि आप सभी ने बहुत आत्मीय स्वागत किया ये अभिनंदन वास्तव में आप सभी का है।आप सभी ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है, जिसके कारण सरकार बनी है। आप सब अभिनंदन के असली हकदार है। मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सभी से वादा करता हूँ कि जो भी वादा हमने किया है। वो सारे वादे पूरे करेंगे। आप सभी ने हमें आश्वस्त किया था, आपने वह करके भी दिखा दिया आपने हमारी सरकार बना दी। आपकी समस्या से हम अवगत हैं, हम आप सभी के बीच से ही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब 15 साल हमारी सरकार रही, तब इसकी शुरुआत हुई थी, हम आपकी मांगों पर मिलकर बात करेंगे, आपके हित में निर्णय लेंगे। मैं आप सभी से थोड़ा वक्त मांगता हूं,आपकी मांगें पूरी होंगी। मोदी की गारंटी पूरी करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अनेक घोषणाएं करते हुए उन्होंने जशपुर जिले के कांसाबेल स्थित तीर्थस्थल तुर्रीघाट के सौंदर्यकरण कार्य के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा। इसके साथ ही खेलों को बढ़ावा देने के लिये कांसाबेल में इंडोर स्टेडियम के निर्माण की घोषणा। उन्होंने कांसाबेल स्थित मुक्ति धाम के सौंदर्यकरण कार्य की घोषणा।

अभा कंवर समाज के लोगों ने जयकारे के साथ किया साय का अभिवादन

रायपुर। कांसाबेल के ग्राम मुडाटोली में अखिल भारतीय कंवर समाज अंचल स्तरीय वार्षिक सम्मेलन सह मिलन समारोह 2024 में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय पहुँचे जहां पर समाज के लोगों ने जयकारे के साथ उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय, पत्थलगांव की विधायक श्रीमती गोमती साय, समाज के श्री सालिक साय, आर पी साय आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने भूमकाल विद्रोह के महानायक और आदिवासी समाज के श्री गुण्डाधुर के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था में हुआ सुधार : श्रीवास्तव

यूपीए ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, बल्कि देश को लूटा भी है

रायपुर। अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्री जी द्वारा जारी किया गया श्वेत पत्र सच्चाई का वो आईना है जिससे कांग्रेस पार्टी के एक परिवार ने देश के सामने नहीं आने दिया था। श्वेत पत्र इस बात की साक्षी है कि 2004 और 2014 के बीच की कांग्रेस की यूपीए सरकार की अवधि की तुलना में 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार हुआ। यूपीए ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, बल्कि यूं कहिये कि देश को लूटा। उक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहीं। इस अवसर पर प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ,उमेश घोरमोड़े मौजूद थे।

श्रीवास्तव ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार से एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था विरासत में मिलने के बावजूद यूपीए ने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे गैर-निष्पादित अर्थव्यवस्था में बदल दिया, इसकी जानकारी हमें इस श्वेत पत्र में मिलती है। कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान देश की जो बदहाल आर्थिक स्थिति थी, उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं उस वक्त सरकार का नेतृत्व कर रहे लोग भी थे। पीएम से लेकर सुपर पीएम तक। देश ने उस वक्त 2जी घोटाला देखा, कोयला घोटाला देखा, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला देखा, सत्यम घोटाला देखा, ट्रक घोटाला देखा, कॉमनवेल्थ घोटाला देखा, कैश फॉर वोट घोटाला देखा, आदर्श घोटाला देखा, शारदा चिटफंट घोटाला देखा, आईएनएस मीडिया मामला देखा, एयरसेल-मैक्सिस घोटाला देखा, एंट्रिक्स-देवास घोटाला देखा, लैंड फॉर जॉब घोटाला देखा। 15 घोटाले कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान 2004 से 2014 के कालखंड में हुए। हमारी सरकार ने आने के साथ ही लोगों को अच्छे लगने वाले निर्णयों की जगह ऐसे निर्णय लिए जो लोगों के लिए अच्छे हों। इसका हमने प्रतिफल भी देखा। हमने देखा कि शौचालय बनने से भी देश की जीडीपी बढ़ सकती है, लोगों के लिए घर बनाने से भी देश की जीडीपी बढ़ सकती है, घर में बिजली, पानी, गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड देने से भी देश की आर्थिक विकास दर में इजाफा हो सकता है। तब देश ने 2जी घोटाला देखा अब, हमारे पास सबसे कम दरों के साथ 4जी के तहत आबादी का व्यापक कवरेज है और 2023 में दुनिया में 5जी का सबसे तेज रोलआउट है।

उन्होंने कहा कि तब की तुलना में बजटीय पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 24 (आरई) तक पांच गुना से अधिक बढ़ गया है बिना इसके बेसिक स्ट्रक्चर में फेरबदल किये बिना। एफडीआई यानी फर्स्ट डेवलप इंडिया। 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया। यह 2005-2014 के दौरान आए एफडीआई से दोगुना था। हम विदेशी पार्टनर्स से बाइलैट्रल इनवेस्टमेंट ट्रीटी (द्विपक्षीय निवेश के लिए समझौता) कर रहे हैं। बेलगाम राजकोषीय घाटे ने देश की अर्थव्यवस्था को एक आर्थिक संकट की ओर ढकेल दिया। अपने राजकोषीय कुप्रंधन की वजह से यूपीए सरकार का राजकोषीय घाटा अंत में अपेक्षा से कहीं ज्यादा हो गया, और बाद में यह 2011-12 में अपने बजट की तुलना में बाजार से 27 प्रतिशत अधिक उधार लेने लगी। आज राजकोषीय घाटे को हम तमाम चुनौतियों के बावजूद 5 प्रतिशत के आसपास रखने में सफल हुए हैं।

संक्षिप्त समाचार

रेलवे स्टेशन पर गलती से चली गोली में आरपीएसएफ जवान की मौत,

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को रेलवे सुरक्षा विशेष बल (आरपीएसएफ) का सर्विस हथियार गलती गोली चल जाने से एक जवान की मौत हो गई और एक यात्री घायल हो गया। अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह करीब छह बजे हुई जब एक उपनिरीक्षक के नेतृत्व में आरपीएसएफ की एक टीम एस्कॉर्ट ड्यूटी के बाद सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन से उतर रही थी। जानकारी के मुताबिक, जब कांस्टेबल दिनेश चंद्र (30) ट्रेन के एस-2 कोच से बाहर निकल रहे थे, तो उनका सर्विस हथियार गलती से चल गया और एक गोली उनकी छाती में लगी। उन्होंने बताया कि एक यात्री की पहचान मोहम्मद दानिश के रूप में हुई है, जो ऊपरी बर्थ पर सो रहा था, उसके पेट में भी चोटें आईं। उन्होंने बताया कि दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कांस्टेबल की मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि मृतक जवान राजस्थान का रहने वाला था और मामले की जांच जारी है।

मंत्री दयाल दास के बंगले में एक आरक्षक ने गोली मारकर की खुदकुशी

रायपुर। राजधानी रायपुर में मंत्री बंगले में एक आरक्षक ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया है। इससे इलाके में सनसनी फैल गई है। यह पूरा मामला गंज थाना क्षेत्र का है, जहां तड़के तीन बजे मंत्री दयाल दास बघेल के स्टेशन रोड स्थित बंगले में सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया है। पुलिस जवान की आत्महत्या के पीछे की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक कॉन्स्टेबल रोहित सलामे एक सप्ताह पहले 25 दिन छुट्टी से लौटा था। घटना की रात जवान अपनी ड्यूटी दो बजे खत्म कर लिया था। रेस्ट करने के लिए गार्ड रूम गया था। उसने रात को 2 बजे ब्रश भी किया। इसके बाद रोहित सलामे आत्मघाती कदम उठा लिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। देर रात घटना की सूचना मिलने पर रायपुर एसएसपी संतोष सिंह, कंपनी कमांडर नेहरू राम साहू, डीएसपी लाइन निलेश द्विवेदी, आरआई वैभव मिश्रा और गंज थाना प्रभारी आशीष यादव घटना स्थल पर पहुंचे। घटना के संबंध में पुलिस जांच में जुट गई है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री साय ने किया नमन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने एकात्म मानववाद के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कहा है कि पं. दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे युगदृष्टा थे, जिनके विचारों व सिद्धांतों ने देश को एक प्रगतिशील विचारधारा देने का काम किया। श्री साय ने कहा कि उनकी विचारधारा राष्ट्र के पुनर्निर्माण और भारत के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए थी। उनके अंत्योदय सिद्धांत पर चलकर हम समस्त जनमानस का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे सदैव हमारे प्रेरणास्त्रोत रहेंगे।

एनजीओ की बैठक शहीद स्मारक भवन में 12 को

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह टॉक-टू-रायपुर कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। इस चर्चा में सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स, यू ट्यूबर्स , ब्लॉगर्स भी सम्मिलित होंगे । यह आयोजन रजबंधा मैदान स्थित नगर निगम के शहीद स्मारक ऑडिटोरियम में सोमवार, 12 फरवरी को शाम 5 बजे आयोजित है।

एक सड़क दुर्घटना पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति तोड़ देती है: न्यायमूर्ति सप्रे

■ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से दुर्घटनाओं पर लग सकता है अंकुश वाहन चालक हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाएं

दुर्ग। एक सड़क दुर्घटना पूरे परिवार की आर्थिक रीढ़ तोड़ देती है यह बात माननीय न्यायमूर्ति श्री अभय मनोहर सप्रे अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी (पूर्व न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया) नई दिल्ली ने दुर्ग के कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज संयुक्त सड़क सुरक्षा संबंधित आयोजित बैठक में कही। बैठक में पुलिस विभाग द्वारा पावरपाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सड़कों की स्थिति एवं दुर्घटनाओं के कारणों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चिन्हित ब्लैक स्पॉट और सुधारात्मक कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया गया। बैठक में संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर और कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी भी सम्मिलित हुई।

बैठक में परिवारों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाली सड़क दुर्घटना रोकने हेतु आइडियल मॉडल बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के शादियों में डिलीवरी वाहनों के परिवहन पर रोक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने पर विचार किया गया। सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए बसों की व्यवस्था के साथ ही स्कूल-कालेज और कार्यालयों में दुपहियां वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यतः सुनिश्चित किये जाएंगे। प्रेशर हॉर्न पर कड़ी कार्यवाही करने, सड़कों पर विचरण करने वाले आवारा पशुओं की रोकथाम हेतु गौठान एवं कांजी हाऊस में व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सभी सड़कों को गुणवत्तापूर्वक बनाने पर जोर दिया गया। सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने हेतु ट्रैफिक पार्क भी बनाया जाएगा। सड़क दुर्घटना होने पर दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को तत्काल उपचार (गोल्डन टाइम पर) उपलब्ध कराने स्वास्थ्य विभाग को पहल करने निर्देशित किया गया। बैठक में नगर निगम भिलाई के आयुक्त श्री देवेश ध्रुव, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री लोकेश चन्द्राकर, जिला परिवहन अधिकारी श्री शैलाब साहू, ट्रैफिक डीएसपी श्री सतीश ठाकुर सहित लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

महतारी वंदन योजना के लिए राज्य में 35 लाख 49 हजार से अधिक महिलाओं ने भरा आवेदन

रायपुर। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ की गई महतारी वंदन योजना के लाभ के लिए बड़ी संख्या में आवेदन भरने का सिलसिला जारी है। इस योजना के तहत प्रदेश में 35 लाख 49 हजार 561 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं से आवेदन लिए जा रहे है। प्रदेश भर में फार्म भरने के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में आवेदन कर रही हैं। महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सभी जिलों में लग रहे कैंपों में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। महिलाओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हर महीने मिलने वाली एक हजार रूपए की राशि से वह अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगी और सम्मानजनक जीवन निर्वाह कर सकेंगी। महतारी वंदन योजना के तहत वर्ष 2024-25 के बजट में 117 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रतिवर्ष महिलाओं को 12000 रूपए मिलेगा।

जिलावार प्राप्त आवेदन- महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक बालोद जिले में एक लाख 24 हजार 986, बलौदाबाजार में एक लाख 40 हजार 06, बलरामपुर में एक लाख 12 हजार 561, बस्तर में एक लाख 22 हजार 610, बेमेतरा में एक लाख 54 हजार 61 आवेदन जमा किए जा चुके हैं। इस प्रकार बीजापुर में 10011, बिलासपुर में एक लाख 67 हजार 48, दंतेवाड़ा में 45 हजार 39, धमतरी में एक लाख 10 हजार 49, दुर्ग में दो लाख 24 हजार 303, गरियाबंद में एक लाख 18 हजार 939, जांजगीर में एक लाख 85 हजार 144, जशपुर में एक लाख 11 हजार 260, कांकेर में 66 हजार 594, कवर्धा में एक लाख 16 हजार 592, कोंडागांव में 91 हजार 76, कोरबा में एक लाख 13 हजार 219, कोरिया में 39 हजार 672, महासमुंद में दो लाख 59 हजार 976, मुंगेली में एक लाख 7 हजार 365, नारायणपुर में नौ हजार 947, रायगढ़ में 86 हजार 312, रायपुर में दो लाख 79 हजार 857, राजनांदगांव में एक लाख 24 हजार 712, सरगुजा में एक लाख 10 हजार 871, सुकमा में 26 हजार 412, सूरजपुर में एक लाख 35 हजार 320, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 68 हजार 302, सक्ती में 82 हजार 763, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में 66 हजार 181, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में 24 हजार 39, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 26 हजार 43, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में एक लाख 33 हजार 291 आवेदन आज तक प्राप्त हो चुके हैं।

मोटे अनाजों की खेती पर सरकार का जोर

मिलेट्स मिशन किसानों के लिए वरदान, अभियान में छत्तीसगढ़ भी शामिल

रायपुर। सरकार मोटे अनाजों यानी श्री अन्न की खेती पर जोर दे रही है। बड़ी वजह है इसकी खेती में पानी की बहुत कम जरूरत होती है। सरकार इसकी खेती और उपज बढ़ाकर किसानों को सीधा इसका लाभ पहुंचाना चाह रही है। सरकार मोटे अनाजों का इस्तेमाल खाद्य सुरक्षा में भी बढ़ा रही है जिससे इसकी खेती को और अधिक बढ़ावा मिले। दरअसल मोटे अनाज के घरेलू और वैश्विक मांग को बढ़ावा देखते हुए भी सरकार इसकी खेती पर जोर दे रही है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी है।

भारत से मोटे अनाज निर्यात के प्रचार, विपणन और विकास की सुविधा के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की गई है। ईट राइट अभियान के तहत, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) स्वस्थ और विविध आहार के हिस्से के रूप में मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पैदा कर रहा है। भारत सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत राज्यों को राज्य की विशिष्ट जरूरतों के लिए काम कर रही है। इसके अलावा, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में मिलेट मिशन शुरू किए गए हैं।

भारत सरकार ने इसे जन आंदोलन बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं, ताकि भारतीय मोटे अनाज के उत्पादन को विश्व स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए भारत में जी20 की अध्यक्षता, मोटे अनाज पाक कार्निवल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्यक्रम, शेफ सम्मेलन, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की प्रदर्शनी, रोड शो, किसान मेले, अर्धसैनिक बलों के लिए शेफ का प्रशिक्षण, इंडोनेशिया और दिल्ली में आसियान भारत मिलेट्स महोत्सव के दौरान मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है।

अभनपुर के हसदा गांव की वृद्ध महिला की शिकायत का 24 घंटे में हुआ निदान

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह को एनजीओ समर्थ जन कल्याण समिति की अध्यक्ष जया द्विवेदी ने 8 जनवरी को व्हाट्सएप्प संदेश भेजकर अभनपुर विकासखंड के ग्राम हसदा की वृद्ध महिला अजीत बाई रात्रे की समस्या से अवगत कराया था कि नल जल कनेक्शन हेतु गड्ढा खोदकर ठेकेदार द्वारा छोड़ दिया गया है एवं गड्ढे को ढंकने की बजाय लगातार आनाकानी की जा रही है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉ. सिंह ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी रायपुर खंड के कार्यपालन अभियंता को तलब किया और तत्काल समस्या का निदान करने निर्देशित किया। कलेक्टर के कड़े निर्देश के उपरांत निर्माण एजेंसी ने तत्काल अपनी त्रुटि सुधार की एवं वृद्ध महिला को हुई असुविधा के लिए माफी भी मांगी। पीएचई अधिकारियों ने इस संबंध में अपना पालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है। एनजीओ और पीड़ित महिला ने त्वरित पहल के लिए कलेक्टर डॉ. सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया, वहीं कलेक्टर ने ऐसे स्वयंसेवी संगठन की सराहना करते हुए कहा कि आम नागरिकों को सुविधा व सहायता पहुंचाने में एनजीओ की भूमिका बड़ी होती है एवं प्रशासन को जानकारी देकर लोगों को मदद पहुंचाने में समर्थ की तरह सभी एनजीओ भी हमेशा आगे रहें। प्रशासन हर सूचना, शिकायत व सुझाव पर त्वरित कार्यवाही करता है।

परीक्षा का डर छूमंतर पर वर्कशॉप

रायपुर। गांधी चौक स्थित हरिनाथ अकेडमी हॉयर सेकंडरी स्कूल में सामाजिक सांस्कृतिक संस्था नवसृजन मंच और महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का डर छूमंतर विषय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में नवसृजन मंच के अध्यक्ष श्री अमरजीत सिंह छाबड़ा जी ने स्वामी विवेकानंद और हरिनाथ अकादमी के बीच संबंध बच्चों से साझा किया। साथ में संस्था के द्वारा किया जाने वाला सामाजिक कार्य और राष्ट्र निर्माण में युवा के योगदान को विस्तृत पूर्वक समझाया। परीक्षा का डर कैसे दूर हो इस विषय पर वक्ता के रूप में श्री कांतिलाल जैन जी ने बच्चों को विस्तार से पाठ्यक्रम का सरलतम से कठिन की ओर अध्ययन कैसे करें, कलर थेरेपी के द्वारा याददाश्त कैसे बढ़ाए, दिनचर्या को व्यवस्थित रखकर खान-पान का संयम, और मोबाइल की फास्टिंग जैसे मुद्दों पर विचार रखकर परीक्षा के डर को सहजता से दूर होने का उपाय बताया।

मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर देवाशीष मुखर्जी ने जीवन के इस अवस्था का महत्व बताते हुए जीवन भर की सफलता हेतु मेहनत का परिणाम क्या होता है? उसे बड़े ही सरलतम उदाहरण द्वारा समझाया। अपने आगामी 7 वर्षों के परिश्रम को कैसे भविष्य के श्रेष्ठ व्यक्तित्व की प्राप्ति की जा सकती है इसे विस्तार से बच्चों को अपने संस्मरण द्वारा साझा किया। इसके अलावा निर्धारित समय में सुनियोजित सतत अध्ययन से पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के पश्चात अधिक से अधिक रिवीजन करने से निर्मित आत्मविश्वास अपने आप परीक्षा के डर को आसानी से दूर कर देती है।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि., संभाग क्र. 3, डी-1/17, सेक्टर-17, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

निविदा आमंत्रण सूचना

NIT-46/2023-2024/ व ले लि — दिनांक : 30-01-2024

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि:- 16/02/2024 अपरान्ह 5.30 बजे तक
ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि:- 20/02/2024 अपरान्ह 5.30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि:- 21/02/2024 पूर्वान्ह 11.30 बजे तक
निविदाकारों की श्रेणी:- ई-पंजीयन के अंतर्गत श्रेणी 'द' से 'अ' तक

निविदा क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में) अमानत राशि(रू.में) बैंक सालवेंसी (रू.में)
1	2	3
T0210	उपसंभाग अमनपुर के उपखण्ड 01 के अंतर्गत आने विभिन्न मार्गों में बी.टी. पेच रिपेयर कार्य	20.00 15000.00 300000.00
T0211	उपसंभाग अमनपुर के उपखण्ड 02 के अंतर्गत आने विभिन्न मार्गों में बी.टी. पेच रिपेयर कार्य	20.00 15000.00 300000.00
T0212	उपसंभाग क्रमांक 3 के अंतर्गत कचना उपखण्ड में आने वाले विभिन्न भवनों में विशेष मरम्मत एवं लघुमूल गौण कार्य	20.00 15000.00 300000.00

आवेदन के साथ Registation Copy, GST Certificate, Bank Solvency एवं जी.एस.टी. भुगतान का 3 बी प्रस्तुत करना अनिवार्य है निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है। अन्य जानकारी हेतु संभागीय कार्यालय में संपर्क करे

कार्यपालन अभियता
लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 3 रायपुर

जी-07679/3

लो आया मौसम 'दलबदल' का

अमिताभ श्रीवास्तव

आगामी लोकसभा-विधानसभा चुनाव के पहले महाराष्ट्र की राजनीति में इतने दल और इतने गुट तैयार हो गए हैं कि कौन-सा नेता कहां है और कब किस तरफ जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। राज्य में हर नए-पुराने संगठन को मजबूत करने के लिए ऐसे नेताओं की जरूरत है, जो जनता के पैमाने यानी चुनाव मैदान में भी खरे उतरें। इसी कारण हर दल की दूसरे दल में ताक-झांक आरंभ हो गई है और दूसरी ओर नेताओं को भी बेहतर संभावनाओं के विकल्प के तौर पर अनेक दल मिल गए हैं। पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय मुरली देवड़ा के पुत्र पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना में शामिल हो गए, तो दूसरी ओर राज्य के एक और पुराने कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा कर दी है। माना जा रहा है कि वह अजित पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। इसी बीच, विधायक रवींद्र वायकर के शिवसेना (शिंदे गुट) में शामिल होने की खबर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे से लेकर अशोक चव्हाण तक के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चा हवाओं में रह चुकी है। हालांकि दोनों नेताओं ने बार-बार उसे अफवाह ही बताया है। इन बड़े नामों के बीच अनेक क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर प्रभाव रखने वाले नेता भी हैं, जो पाला बदल रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो चुनाव के पहले दल-बदल एक सामान्य शक्ति प्रदर्शन की प्रक्रिया है, लेकिन राज्य में दो बड़ी पार्टियों के टूटने के बाद से इसे सहज ही नहीं देखा जा रहा है। इसे कमजोरी और मजबूती की नजर से भी देखा जा रहा है। इसे भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने का भी रास्ता बताया जा रहा है। कुछ हद तक इधर-उधर जाने वाले नेताओं में आरोपित नेताओं की संख्या अधिक है। आगे यह भी साबित हुआ है कि उन पर चलने वाले मामले भी ठंडे बस्ते में गए हैं। इसलिए नेताओं का सहज ही हृदय परिवर्तन होना नहीं माना जा सकता है। दूसरी वजह यह भी है कि कुछ नेता अपनी पार्टी के विभाजन के बाद मूल पार्टी में इस आशा से रह गए थे कि उन्हें महत्व अधिक मिलेगा। कालांतर में उन्हें वह नहीं मिला। इसी प्रकार कुछ नेता पार्टी में विभाजन के बाद एक जोश में दूसरे दल में चले गए थे, जो बाद में महंगा साबित हुआ। इसलिए उन्हें मूल पार्टी में जाना उचित लग रहा है। इस सब के बीच चुनावी संभावना है, जिसको लेकर नेताओं का असली वजन तौला जा रहा है। कुछ वजनदार नेता इसी वजह से पार्टियों की 'डिमांड' में हैं। उनसे कुछ चुनावी सीटों का भाग्य आसानी से तय हो जाएगा। आम तौर पर बेहतर संभावनाओं या मुश्किल परिस्थितियों में ही दलबदल देखा जाता है। यदि किसी ज्यादा ताकतवर दल में जाने से भविष्य सुरक्षित हो जाता है तो बदलाव उचित ठहराया जा जाता है, या फिर किसी दल में अत्यधिक उपेक्षित किए जाने पर किसी दल में सम्मानजनक प्रवेश का मिलना सही माना जाता है। इस बात के राज्य में नारायण राणे, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, राधाकिशन विखे, नाना पाटोले, प्रवीण दरेकर जैसे अनेक उदाहरण हैं। इनके अलावा जयसिंहराव गायकवाड़, हर्षवर्धन पाटिल, चित्रा वाघ जैसे भी उदाहरण हैं, जो दलबदल के बाद अपने पुनर्वास के इंतजार में बैठे हैं। किंतु इस बार स्थितियां पुराने तरह के दलबदल से अलग हैं। पहले तो राज्य के दोनों गठबंधनों को अपनी सीटों का बंटवारा तय करना है और उसके बाद अपने उम्मीदवार तय करना है। इस चुनाव में कार्यकर्ता तक की निष्ठा की परीक्षा का परिणाम मतदाता देंगे। उनका पाला बदलना सही था या फिर गलत था, वह चुनाव तय करेंगे। इसलिए भी उम्मीदवारों को लेकर चिंता का वातावरण सभी तरफ है। केवल नाम के उम्मीदवार खड़े करने से अलग पार्टी बनाने या मूल पार्टी बचाने का मकसद साफ नहीं होगा। उसके लिए चुनावी ताकत का भी प्रदर्शन करना होगा। पार्टियों के विभाजन के बाद मतदाताओं के मन का हाल किसी को पता नहीं है। मूल दलों में बड़े और पुराने नेताओं की उपस्थिति का मतदाताओं पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक असर का भी अनुमान नहीं लगाया जा पा रहा है। कार्यकर्ताओं की निष्ठा पर प्रभाव पड़ने का कोई अंदाज नहीं लगा पा रहा है। चुनाव में अनेक इलाकों में त्रिकोणीय से लेकर चतुष्कोणीय मुकाबलों की संभावना है। संभावना यह भी है कि अनेक सीटों पर बहुत कम अंतर से भी फैसला हो सकता है। यदि अंदाज किसी भी तरह से गलत साबित हुआ तो राज्य की राजनीति के सारे समीकरण बदल जाएंगे।

'चार सौ पार' के दावे में सियासी प्रबंधन

अजय बोकिल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के उत्तर में संसद में आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा अपने दम पर 370 और एनडीए द्वारा 4 सौ के पार सीटें जीतने का जो दावा किया गया था, उसका आधार मोदी सरकार द्वारा भारत रत्न सम्मानों की झड़ी तथा विपक्षी तथा दूसरे दलों को अपनी छतरी में लाने के अभियान से समझा जा सकता है। वैसे प्रधानमंत्री ने जो दावा कर रहे हैं, वह जमीन पर कितना उतरेगा, यह तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे, लेकिन उसे साकार करने की दिशा में स्वयं प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी भाजपा जिस तरह जमीन आसमान एक किए दे रही है, उससे लगता है कि यह सच हो भी सकता है। भले ही चुनाव पूर्व किए जा रहे ओपीनियन पोल के नतीजे अभी इस दावे को दूर की कौड़ी ही बता रहे हों।

बहरहाल, भाजपा की चार सौ पार की यह रणनीति कई स्तरों पर नजर आती है और साम-दाम-दंड-भेद से प्रेरित है। नैतिक आधार पर इसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर वह सफल होती दिखती है। यूं भी राजनीति मूलतः सत्ता का खेल है और कुर्सी ही इसका अंतिम साध्य है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे बखूबी समझते हैं। इसीलिए दो कदम आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटने में भी उन्हें गुरेज नहीं है।

आज क्या हासिल होगा, यही उनका प्राथमिक लक्ष्य है। कल क्या होगा, भावी इतिहास इसका आकलन किस रूप में करेगा, नीति शास्त्र में उसे कहां जगह मिलेगी, नियम-कानूनो की लक्ष्मण रेखाओं की सुविधाजनक व्याख्या कैसे की जाएगी, आज लोकतंत्र की आधारभूत संस्थाओं के हाथ किसे सेल्यूट कर रहे हैं, जैसे सवाल आगे भी उठेंगे लेकिन मोदी राजनीति शास्त्र में इन सवालों की चिंता किए बगैर बहुतांश की जनाकांक्षा को किस भाव से पढ़ा जाए और उसे किस तरह अपने पक्ष में मोड़ा जाए, यह हिकमत ही नया पॉलिटिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और मोदी इस प्रौद्योगिकी के मास्टर हैं।

इसी बाजीगरी को इस साल घोषित पांच भारत रत्नों में बूझने की कोशिश मोदी के आलोचक कर रहे हैं। हालांकि, भारत रत्न जैसा सर्वोच्च पुरस्कार जाति, धर्म, समुदाय और

क्षेत्रीय दुराग्रहों से परे है और देश की असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। लेकिन इस बार दिए गए पांचो भारत रत्नों में जाति और भौगोलिक क्षेत्र के महीन समीकरण साधने का भाव भी निहित है। भले ही घोषित तौर पर यहा कहा जाए कि हमने वैचारिक मतभेदों के परे जाकर भारत रत्न पुरस्कार दिए हैं। लेकिन न साधकर भी बहुत कुछ साधने की सियासी कारीगरी इसमें साफ झलकती है।

अब सवाल यह है कि क्या भाजपा को लोकसभा चुनाव में इसका लाभ वोटों के रूप में मिलेगा, इसका जवाब पाने के लिए हमे नतीजों का इंतजार करना होगा। इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि भारत रत्न पुरस्कारों में निहित राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ववर्ती अनुभवों में बहुत ज्यादा फलित होती नहीं दिखी है। इसका कारण शायद यह भी है कि पहले के कर्णधारों ने भारत रत्नों के जरिए राजनीतिक हित साधने की झीनी कोशिश जरूर की थी, लेकिन वह उतनी शिद्दत से नहीं थी, जैसी कि इस बार दिखती है। दूसरे, जो पुरस्कार दिए गए हैं या और भी दिए जा सकते हैं, वो ठीक चुनाव के मुहाने पर हैं।

लिहाजा इसका कुछ न कुछ असर होने की पूरी संभावना है, जिसका फायदा भाजपा और एनडीए को किसी न किसी रूप में होगा। तीसरे, विचार और आग्रहों के स्तर पर जैसी जबर्दस्त गोलबंदी ऊपर से नीचे तक अब दिखाई दे रही है या करने की कोशिश की जा रही है, वैसी एक दशक पहले तक नहीं थी। जिस होशियारी से ये भारत रत्न दिए गए हैं, उसकी आलोचना मोदी विरोधी भी खुलकर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इसमें खतरा यह है कि अगर यह दांव चल गया तो आने वाले समय में किसी भी प्रधानमंत्री को 'भारत रत्न लो और वोट दो' की नीति पर ही काम करना होगा। इसकी शुरूआत हो भी चुकी है।

मायावती ने दलितों के नेता कांशीराम और शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। इनके नामो की घोषणा हो भी सकती है बशर्ते ये सब एनडीए के शामियाने में अपना राजनीतिक स्टॉल लगा लें। दूसरे शब्दों में कहें तो अब किसी विशिष्ट क्षेत्र में अन्यतम योगदान के जरिए देश सेवा के लिए भारत रत्न देकर राष्ट्रीय कृतज्ञता जताने का दौर धुंधला चुका है। यह असंभव नहीं कि भारत रत्न अब जातीय/सामुदायिक अथवा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व या फिर राजनीतिक लामबंदी की योग्यता के आधार पर ही दिए जाने लगें।

इसमें शक नहीं कि लोकसभा चुनाव में चार सौ पार का आंकड़ा हासिल करने के लिए भाजपा अपना एनडीए कुनबा बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रही है। पहले जदयू का लौटना, अब रालोद का एनडीए में शामिल होना, पंजाब में अकाली दल को लौटाने की कवायद इसी का हिस्सा है। उधर दक्षिण में पी.वी. नरसिंहराव को भारत रत्न देने का स्वागत पूर्व सत्तारूढ़ रही भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष केसीआर ने किया है। केसीआर की पार्टी ने तीन साल पहले पी.वी. नरसिंहराव की जन्मशती धूमधाम से मनाई थी और उन्हें 'तेलंगाना का गौरव' और 'भारतमाता का परम प्रिय पुत्र' कहा था। तब कांग्रेस खामोश ही रही थी।

हालांकि, अब नरसिंहराव को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद कांग्रेस यह कह रही है कि उन्हें प्रधानमंत्री तो हमने ही बनाया था। पी.वी. नरसिंहराव अविभाजित आंध्र के मुख्यमंत्री थे। ऐसे में आंध्र में भी इसका कुछ तो संदेश गया ही है। खासकर तब कि जब भाजपा और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी फिर साथ आने की बात चल रही है। इसी तरह वर्तमान संदर्भों में महान कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देना विज्ञान प्रतिभा के सम्मान से ज्यादा तमिलनाडु की जनता को राजनीतिक संदेश देना ज्यादा है। हालांकि वहां की द्रविड राजनीति में अभी भी भाजपा के लिए कोई खास जगह नहीं है, लेकिन यह रेत में घरौंदा बनाने की कोशिश जरूर है।

एक बात साफ है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए केवल राम लहर, हिंदुत्व और सुनहरे आर्थिक सपनो के भरोसे नहीं है। वह इसी के समानांतर गरीब कल्याण, रेवड़ी कल्चर, सियासी गोलबंदी, धार्मिक ध्रुवीकरण, मोदी के वैश्विक नेता बनने, भारत के विश्व गुरू होने की दिशा में आगे कूच करने तथा युवाओं का सपना सच होने के दावों के टूल्स का भी भरपूर उपयोग कर रही है। इस शोर में गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विकास में छिपी विषमता, जातीय और साम्प्रदायिक तनाव जैसे मुद्दे तूती की आवाज बनकर रह जाते हैं।

इसमें दो राय नहीं कि बीते एक दशक में भाजपा ने यह साबित कर दिया है कि चुनाव प्रबंधन में उसका कोई सानी नहीं है और उस पर राजनीतिक बढ़त हासिल करनी है तो विरोधी दलों को अब भी नए उपकरण, नए तरीके और जुमले अपनाने होंगे। भाजपा को भाजपा के पिच पर नहीं हराया जा सकता।

प्रधानमंत्री के दावे में एक पेंच भाजपा द्वारा 370 सीटें अपने दम पर जीतने का है। यह आंकड़ा कहां से और कैसे आया? यह केवल शोशेबाजी है या फिर इसके पीछे भी कोई रणनीति है? यह सवाल इसलिए भी मौजूं है क्योंकि हाल में हुए ओपिनियन पोल भाजपा और एनडीए को तीसरी बार सत्ता तो दिला रहे हैं, लेकिन भाजपा की सीटों में बेहद मामूली इजाफा दिखा रहे है। 2019 में भाजपा ने अकेले 303 सीटें जीती थीं। यानी 370 तक पहुंचने के लिए उसे 67 सीटें और चाहिए। ये कहां से आएंगी?

जिन राज्यों में भाजपा एक या दो नंबर पर है, वहां वह अधिकतम सीटें पहले ही जीत रही है। अर्थात 67 सीटें उसे उन राज्यों में जीतनी होंगी, जहां क्षेत्रीय दल सत्ता में हैं। यह तभी संभव है, जब मोदी और रामलला की जबर्दस्त आंधी चले। ऐसा फिलहाल तो नहीं लग रहा है। लेकिन यदि ऐसा कोई अंडर करंट है तो वह नतीजों में ही झलकेगा। संभव है कि पीएम द्वारा 370 का आंकड़ा बताने के पीछे कश्मीर से धारा 370 हटाने का संदेश निहित हो। यह जताने की कोशिश भी हो सकती है कि हमने अपने कोर एजेंडे को पूरा कर दिया है। लिहाजा हम ही तीसरी बार भी सत्ता के दावेदार हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-4)

गतांक से आगे...

तदनन्तर उन (विराट् पुरुष) भगवान् नारायण ने एक अन्य कामना से संकल्प युक्त हो अन्तःस्थ मन से ध्यान किया। अन्तःस्थ होकर ध्यान करने से उनके ललाट से त्रिनेत्रयुक्त, हाथ में त्रिशूल धारण किये हुए पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस ऐश्वर्यशाली पुरुष के शरीर में यश, सत्य, ब्रह्मचर्य, तप, वैराग्य, नियन्त्रित मन, श्री- सम्पन्नता एवं ओंकार सहित व्याहृतियाँ, ऋ, यजुः, साम, अथर्व आदि चारों वेद तथा समस्त छन्द प्रतिष्ठित थे। इसी कारण वह ईशान एवं महादेव के नाम से प्रख्यात हुए।

इसके पश्चात् पुनः उन भगवान् नारायण ने अन्य कामना से अन्तः में स्थित होकर ध्यान किया। उस अन्तःस्थ ध्यान में लीन नारायण के ललाट से पसीने की बूंदें निःसृत होने लगीं। वह पसीना ही चारों ओर फैलकर आपः (प्रकृति का मूल क्रियाशील द्रव्य) रूप में परिणत हो गया। उस आपः से ही तेजोमय हिरण्यगर्भरूप अण्ड की उत्पत्ति हुई और उसी तेज से चतुर्मुख ब्रह्माजी प्रकट हुए।

उन पितामह भगवान् ब्रह्माजी ने (चारों दिशाओं में भिन्न-भिन्न देवों का) ध्यान किया। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके उन्होंने भूः व्याहृति, गायत्री छन्द, ऋग्वेद तथा अग्निदेव का ध्यान किया। पश्चिमाभिमुख होकर भुवः व्याहृति, त्रिष्टुप् छन्द, यजुर्वेद सहित वायुदेव का ध्यान किया। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर स्वः व्याहृति, जगती छन्द तथा सामवेद सहित सूर्य (सविता) देव का ध्यान किया और दक्षिण की तरफ अभिमुख होकर महः व्याहृति, अनुष्टुप् छन्द तथा अथर्ववेद सहित सोम देवता का ध्यान किया।

[यहाँ पितामह के द्वारा जिन-जिनके ध्यान करने का उल्लेख है, वे सभी उसी ध्यान प्रक्रिया से प्रादुर्भूत होते चले गये।]

क्रमशः ...

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय

डॉ. राकेश मिश्र

अपने उच्च विचारों, आदर्शों और त्याग के कारण भारत के लोगों के हृदय में स्थान बनाने वाले और एकात्म मानववाद जैसी विचारधारा और राष्ट्रवादी चिंतन देनेवाले, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ व राष्ट्रीय जनसंघ के संस्थापकों में शामिल पंडित दीनदयाल उपाध्याय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेता भारत के सबसे तेजस्वी एवं यशस्वी चिंतकों में से एक रहे हैं।

25 सितम्बर सन् 1916 को चंद्रभान, फ़राह, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। 1937 में कानपुर में अपनी बी.ए. की पढ़ाई के दौरान वे अपने सहपाठी बालूजी महाशब्दे और सुंदर सिंह भंडारी के साथ मिलकर समाज सेवा करने लगे। इन्ही दिनों वे

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार जी व भाऊराव देवरस जी से संपर्क में आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित होकर संघ से जुड़ गए। संघ की शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वे 1939 में संघ के 40 दिवसीय नागपुर शिविर का हिस्सा बने।

भाऊराव देवरस से प्रेरणा पाकर सन 1947 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लखनऊ में राष्ट्रधर्म प्रकाशन स्थापित किया, जिसके अंतर्गत मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म प्रकाशित एवं प्रसारित की जाने लगी। बाद में पांचजन्य साप्ताहिक और दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का भी प्रकाशन यहां से हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक अच्छे साहित्यकार व लेखक भी थे। अपने जीवन में सफ़लता की अनेक सीढियां चढ़ने के बाद पंडित जी ने स्वयं को पूर्ण रूप से देश के प्रति अर्पित कर दिया। 21 अक्टूबर सन् 1951 में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की तो 1951 से 1967 तक वे भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। 29 दिसम्बर 1967 को उन्हें पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। विडम्बना ही कही जायेगी कि पंडित जी सिर्फ 44 दिनों तक ही बतौर अध्यक्ष कार्य कर पाए। 1952 में कानपुर में हुए पार्टी के पहले अधिवेशन में पंडितजी को महामंत्री निर्वाचित किया गया। यहीं से अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई। पंडित जी ने प्रथम अधिवेशन में ही अपनी वैचारिक क्षमता का परिचय देते हुए सात प्रस्ताव प्रस्तुत किये और सभी को पारित कर दिया गया। उनकी कार्यक्षमता, परिश्रम और परिपूर्णता के गुणों से प्रभावित होकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था- यदि मुझे ऐसे दो दीनदयाल मिल जाएं तो मैं देश का राजनीतिक मानचित्र बदल दूंगा। डॉ. साहब की यही बातें पंडित जी का हौंसला और भी बढ़ाती गई। पंडितजी राष्ट्रनिर्माण व जनसेवा में इतने लीन थे कि उनका कोई व्यक्तिगत जीवन ही नहीं रहा, बांकी का जीवन संघ और जनसंघ को मजबूत बनाने और इन संगठनो के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने में अर्पित कर दिया। दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार उन्हें औरों से बिल्कुल अलग साबित करते हैं। उनकी अवधारणा और चिंता का विषय था कि लम्बे समय तक की गुलामी के पश्चात कहीं पश्चिमी विचारधारा भारतीय संस्कृति पर हावी न हो जाए। 11 फ़रवरी 1968 को पंडित जी इस संसार को छोड़ गये।

लोकतंत्र के लिए मजाक बनता पाकिस्तान

सिद्धार्थ शंकर गौतक

आखिरकार जनसंख्या में दुनिया के पांचवे सबसे बड़े देश पाकिस्तान में दिखावे के लिए ही सही किंतु लोकतांत्रिक चुनाव हुए। गुरुवार को हुए चुनावों में नेशनल असेंबली की 336 सीटों में से 266 सीटों पर मतदान हुआ जिन पर 5121 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान में अभी चुनाव नहीं होने हैं। इस चुनाव में गैर मुस्लिम घोषित 5 लाख अहमदियाओं ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है तो बलूचों के साथ पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों का मामला भी सुर्ख़ियों में है। हालांकि मतदान से 24 घंटे पूर्व हुए 2 धमाकों में 30 लोगों की मौत ने यह भी अंदेशा जता दिया था कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तो नहीं रहने वाली।

पाकिस्तान से लगे अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर सील हैं तो 6.50 लाख सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बैन कर दिया गया है जिससे वहां की चुनावी गड़बड़ियों का पता बाहरी दुनिया को न चल सके। बदहाल अर्थव्यवस्था सुधारने के नाम पर नवाज शरीफ, तो जनकल्याणकारी योजनाओं के नाम पर बिलावल भुट्टो चुनावी मैदान में हैं। वहीं इमरान खान की पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही क्योंकि चुनाव आयोग ने उसका चुनाव चिन्ह ही जब्त कर लिया है। कुल मिलाकर पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में हो रहे चुनाव से किसी को कोई खास उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान में लोकतंत्र का मजाक बनता जा रहा है।

पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिए संभवतः कोई स्थान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब-जब पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत होने की स्थिति में आया है, सेना अथवा न्यायालय ने उसे पटरी से उतार दिया है। पाकिस्तान के इतिहास का पहला तख्तापलट 1958 में हुआ था जब पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने प्रधानमंत्री फिरोज खान नून की सरकार को भंग करते हुए मार्शल लॉ लागू कर आर्मी कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान

को देश की बागडोर सौंप दी थी। हालांकि तेरह दिन बाद ही अयूब खान ने तख्तापलट करते हुए सिकंदर मिर्जा को ही राष्ट्रपति पद से हटा दिया था। इसके बाद तो मानो पाकिस्तानी सेना के मुंह में लोकतंत्र का खून ही लग गया था। 1977 में ऑपरेशन फेयर प्ले से नाम से मशहूर तख्तापलट में जनरल जिया उल हक ने प्रधानमंत्री जुल्फीकार अली भुट्टो को पद से हटा दिया था। 1988 के बाद से तो पाकिस्तान में कोई भी निर्वाचित प्रधानमंत्री अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाया है। 1988 में बेनजीर भुट्टो की सरकार को 1990 में राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया गया।

भुट्टो सरकार के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने किंतु 1993 में इस्तीफा देना पड़ा। उनके इस्तीफे के बाद एक बार पुनः बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनीं किंतु एक बार पुनः 1996 में राष्ट्रपति ने उनकी सरकार भंग कर दी। इसके बाद फिर नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने किंतु सेना से उनकी पटरी नहीं बैठी और सैन्य प्रमुख परवेज मुशर्रफ द्वारा उनकी सरकार का तख्तापलट कर दिया गया। इसके बाद नवाज शरीफ को जेल जाना पड़ा और छूटने के बाद उन्होंने लंबा समय निर्वासन में बिताया। इसी प्रकार 2008 में युसुफ रजा गिलानी को पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय ने अवमानना का दोषी मानते हुए उन्हें संसद से अयोग्य करार दिया जिसे न्यायिक तख्तापलट की संज्ञा दी गई।

नवाज शरीफ (2013-2017) भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोग्य ठहराए जा चुके हैं जबकि इमरान खान (2018-2022) को सेना के इशारे पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की आड़ में हटाया गया। हालांकि अब जाकर नवाज शरीफ के सेना से संबंध सुधरे हैं और वे पुनः पाकिस्तान के चुनाव में बतौर प्रधानमंत्री चेहरा खड़े हुए हैं। उनकी पारिवारिक पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के प्रत्याशी इस समय पाकिस्तानी जनता की भी पसंद हैं। नवाज की पार्टी के चुनाव चिन्ह टाइगर को देखते ही पाकिस्तानी अवाम शेर आया...शेर आया के नारे लगा रही है जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। अब नई निर्वाचित सरकार को सेना और न्यायालय का कितना साथ मिलता है, यह किसी को नहीं पता। लेकिन कभी अपनी कहर बरपाती तेज गेंदबाजी से विरोधियों के छक्के छुड़ाने वाले इमरान खान को उनके देश की सेना ने ही क्लीन बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी बनाकर इमरान खान ने जो छवि पाकिस्तानी जनता और वैश्विक समुदाय में बनाई थी, सेना के चलते वह तार-तार हो चुकी है।

वर्तमान में अदियाला जेल में बंद इमरान को 4 क्रिमिनल केसों में क्रमशः 03 साल, 10 साल, 14 साल और 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उन पर 150 से अधिक केस चल रहे हैं। उनकी न सिर्फ राजनीति बल्कि उनका पारिवारिक जीवन भी सेना के इशारों पर बर्बाद कर दिया गया है। उनका बुशरा बीवी से निकाह अमान्य करार हो गया है। हालांकि इतना सब होने के बाद भी इमरान खान पाकिस्तान में लोकतंत्र के हिमायतियों के बीच खासे लोकप्रिय हैं किंतु चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह बैट जब्त कर लिया है जिसके कारण उनकी पार्टी के प्रत्याशी 200 से अधिक भिन्न चुनाव चिन्हों पर निर्दलीय लड़ रहे हैं। अब इससे जनता का उन्हें कैसा रिस्पॉन्स मिलता है और चुनाव जीतने के बाद भी क्या उनकी प्रतिबद्धता इमरान खान के प्रति रहेगी, यह बड़ा प्रश्न है। फिलहाल तो इमरान खान ही पाकिस्तान में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरे हैं। एआई की सहायता से तैयार हुए इमरान खान के वीडियो पार्टी कार्यकर्ताओं से साथ ही जनता को संदेश दे रहे हैं। उनकी पार्टी का सोशल मीडिया पर प्रचार चल रहा है।

पाकिस्तान में चुनाव इतने अनोखे ढंग से होते हैं कि वहां मूल मुद्दों की चर्चा ही नहीं होती। इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। पाकिस्तान की 40 प्रतिशत से अधिक जनता अर्थात 9 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रहती है किंतु चुनाव में इस बात की कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। कर्ज के बोझ तले दब चुका पाकिस्तान कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया है कि वित्त वर्ष 2023 में पाकिस्तान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए) से सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला देश है। पाकिस्तान सरकार का कर्ज सालाना आधार पर 34.1 प्रतिशत वृद्धि के साथ अप्रैल, 2023 के अंत में 58.6 लाख करोड़ रुपये हो गया था। इसके बाद भी उसने आईएमएफ से 700 मिलियन डॉलर का कर्ज बेहद कड़ी शर्तों पर लिया। कर्ज और तंगहाली के अलावा पाकिस्तान तालिबान और ईरान की दोहरी चुनौती से भी जूझ रहा है।

पाकिस्तान सेना और आईएसआई की तकरार चरम पर पहुँच चुकी है तो वहीं ईरान के साथ उसका सीमा संघर्ष बमबारी पर आ गया है किंतु पाकिस्तान में चुनाव इस बात पर हो रहा है कि नवाज शरीफ सेना के साथ मधुर संबंध कब तक रख पाएंगे अथवा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो का भविष्य क्या होगा? इमरान खान क्या अब सारा जीवन जेल की सलाखों के पीछे काटेंगे या उनकी भी पर्दे के पीछे सेना से कोई डील हो जाएगी? पाकिस्तान के चुनाव परिणाम कुछ भी रहें, न तो उसकी सेना पर कोई असर पड़ने वाला है और न ही अर्थव्यवस्था पर। पड़ोसी देशों के साथ भी संबंधों में फिलहाल कोई सुधार आता नहीं दिख रहा। ऐसे में पाकिस्तान में लोकतंत्र का झुनझुना पकड़ाकर जनता को पुनः मूर्ख बनाया जा रहा है।

आज का इतिहास

1919 फ्रेडरिक एबर्ट को वाइमर नेशनल असेंबली द्वारा जर्मन वीमर गणराज्य का पहला राष्ट्रपति चुना गया था।
1919 फ्रेडरिक एबर्ट जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गये।
1929 रोमन क्रेश्चन 'को निपटाने में मदद करने के लिए इटली और रोमन कैथोलिक चर्च के होली सी ने वेटिकन सिटी को इटली के भीतर एक स्वतंत्र संप्रभु एनक्लेव के रूप में स्थापित करने के लिए लेटरन संधि पर हस्ताक्षर किए।
1938 बीबीसी ने कैरेल कैपेक के नाटक आर.यू.आर. का एक रूपांतरण प्रसारित किया, जो अब तक का पहला विज्ञान कथा टेलीविजन कार्यक्रम है।
1953 सोवियत संघ ने इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़े।
1963 अमेरिकी में जन्मे कवि सील्विया प्लाथ ने लंदन में आत्महत्या की।
1964 यूनानी में साइप्रियोट और तुर्की साइप्रस निवासियों ने लिमासोल साइप्रस में आपस में लड़ाई से 50 लोग मरे गए।
1968 इस्राइल और जॉर्डन के बीच सीमावर्ती संघर्ष शुरू हुआ।
1968 अमेरिका में टेनेसी, मेम्फिस में लगभग 1,300 अश्वेत स्वच्छता कर्मचारियों की नौकरी से दो काले कर्मचारियों के मारे जाने के बाद, हड़ताल शुरू हुई जो दो महीने तक चली।
1970 जापान ने पहले उपग्रह योसुमि, एक लैम्ब्डा -4 रॉकेट पर लॉन्च किया।
1978 चीन ने अरस्तू, शेक्सपियर और डिकेंस की रचनाओं पर लगा प्रतिबंध हटाया।
1978 न्यूयॉर्क शहर में सोलह एकीकरण चर्च जोड़ों की शादी का आयोजन किया गया।
1979 ईरान का पहलवी राजवंश तब प्रभावी रूप से ध्वस्त हो गया जब सेना ने खुद को %तटस्थ% घोषित कर दिया जब सशस्त्र सड़क लड़ाई में शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के प्रति निष्ठावान सैनिकों को भारी परेशानी हुई।
1979 ईरान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खमेनी का सत्ता पर कब्जा हुआ।
1987 ब्रिटिश एयरवेज का निजीकरण हुआ और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया।
1990 रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता नेल्सन मंडेला, 27 साल का राजनीतिक कैदी, दक्षिण अफ्रीका के पार्ल के पास विक्टर वेरस्टर जेल से रिहा किया गया था।
1990 दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला को 27 साल लंबी कैद के बाद रिहाई मिली।

क्या सचमुच अवैध अतिक्रमण का विरोध ही है हल्द्वानी की हिंसा?

संजय तिवारी

सीएए के विरोध में पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों में 2020 में जिस प्रकार की हिंसा और उपद्रव किया गया था, हल्द्वानी की हिंसा ने उसकी याद ताजा कर दी है। दिल्ली में एक समुदाय विशेष द्वारा बहुत सुनियोजित तरीके से पूर्वी दिल्ली को दंगे की आग में झोंक दिया गया था। उस समय जब पूरा देश शाहीनबाग में कुछ लोगों द्वारा आयोजित सीएए विरोधी प्रदर्शन पर नजर गड़ाये हुए था तब उन्हीं में से कुछ लोग बड़े दंगे की तैयारी कर रहे थे। चुपचाप उन्होंने इतनी बड़ी तैयारी कर रखी थी कि जब हिंसा की शुरुआत हुई तो चार दिनों तक पूर्वी दिल्ली का एक हिस्सा जलता रहा। कुछ वैसा ही मामला हल्द्वानी की हिंसा में भी दिखाई दे रहा है। जिस व्यापक स्तर पर पुलिस और आम जनता के खिलाफ हिंसा का खेल खेला गया है यह अचानक से उग्र हुई भीड़ की हिंसा नहीं है। यह एक सुनियोजित दंगा है जिसके पीछे भरपूर तैयारी दिखाई देती है। दिल्ली दंगों की तर्ज पर ही यहां भी बंदूकों का इस्तेमाल हुआ है। बोतलों का इस्तेमाल पेट्रोल बम बनाने के लिए किया गया है। हिंसा करनेवाले समुदाय के लोगों ने पूरी तैयारी के साथ हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके को तहस नहस करने का प्रयास किया है।

इस हिंसा में दो से छह लोगों के मरने की आशंका है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। घायल होनेवालों में पुलिस बल के लोग भी शामिल हैं। पुलिसवाले खुद वीडियो बनाकर, टीवी पर आकर उस बर्बर और भयानक हिंसा का वर्णन कर रहे हैं जिसमें उनकी जान जाते जाते बची है। बनभूलपुरा पुलिस थाने को पूरी तरह से फूंक दिया गया है। कुछ पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए एक मकान में घुस गये तो दंगाइयों ने उस घर को भी आग लगाने की कोशिश की। उन पर पेट्रोल बम फेंका, पत्थर बरसाये। जब घर नहीं जला पाये तो घर में घुसकर उस मकान मालिक को ही बुरी तरह मारा पीटा जिसने उन पुलिसवालों को जीवन बचाने के लिए शरण दी थी। इनमें शामिल एक महिला पुलिसकर्मी का कहना है कि महिलाओं और पुरुषों की भीड़ छतों और सड़कों से लगातार पथराव कर रही थी। गलियों में जाम लगा दिया गया था ताकि हम बचकर न निकल पायें। बचने के लिए 15-20 पुलिसवाले जब एक घर के अंदर घुस गये तो भीड़ ने उस घर को ही आग लगाने की कोशिश शुरु कर दी। काफी देर बाद हमें वहां से निकालने के लिए फोर्स आयी। जब फोर्स हमें वहां से निकालकर ले जा रही थी तो छतों से फिर से पत्थरबाजी

शुरु हो गयी। कांच की बोतलें भी फेंकी गयी जिससे कई पुलिसवाले घायल हो गये।

स्वयं हल्द्वानी की डीएम वंदना सिंह का कहना है कि जिस प्रकार की हिंसा की गयी है वह बिना सुनियोजित तैयारी के नहीं हो सकती। वंदना सिंह ने मीडिया बात करते हुए स्पष्ट कहा कि यह अतिक्रमण विरोधी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं थी जिसमें किसी समुदाय को जानबूझकर टार्गेट किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त करने की कार्रवाई पहले से चल रही है। कुछ अतिक्रमण हटाये गये और जब यहां पहुंचे तो इस प्रकार की हिंसा की गयी। वंदना सिंह कहती हैं कि स्थानीय लोग इसे मलिक का बगीचा कहते हैं लेकिन सरकारी कागजों में यह सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। असल में जिस मदरसे और उसमें बनी मस्जिद को हटाने के बाद हिंसा शुरु की गयी वह सरकारी जमीन पर बना अवैध अतिक्रमण ही था। इसके पीछे अब्दुल मलिक नामक एक व्यक्ति है जिसने यहां सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से प्लाटिंग भी कर रखी है। प्रशासन जब उस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचा तो वहां तैयारी के साथ पुलिसवालों, नगर निगम कर्मचारियों पर हमला बोल दिया गया। हालात इतने बेकाबू हो गये कि गुरुवार की रात को ही उत्तराखण्ड सरकार ने केन्द्र से अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग के साथ साथ दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी जारी कर दिया था।

लेकिन जिस प्रकार की तैयारी के साथ पुलिसवालों और जन सामान्य पर यह हमला हुआ है क्या सचमुच यह सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मदरसे का ही मामला लगता है? हिंसा की व्यावकता को देखते हुए इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। किसी भी समुदाय द्वारा क्या कुछ घण्टों में हिंसा की इतनी तैयारी की जा सकती है कि पुलिसवालों को भी अपनी जान के लाले पड़ जाएं? यहां पर यह विचार भी आता है कि क्या कोई समुदाय सदैव हिंसा की तैयारी किये बैठा रहता है जो चंद घण्टों में ही ऐसी हिंसा कर बैठता है कि देखते ही गोली मारने का आदेश देना पड़े? लेकिन इन दोनों ही सवालों से इतर एक तीसरा सवाल भी है क्या यह प्रदेश में लागू की गयी समान नागरिक संहिता पर एक समुदाय विशेष द्वारा दिया गया रिएक्शन है? याद करिए दिल्ली दंगों को। वहां भी कपिल मिश्रा के सिर्फ वहां जाने भर को मुद्दा बनाकर इतनी बड़ी हिंसा की गयी थी। उस समय भी घरों से ईंट पत्थर के अलावा पेट्रोल बम फेंके गये थे। कहा यही गया कि कपिल मिश्रा के भड़काने पर दंगा हुआ लेकिन असल मकसद बाद में पुलिस की जांच में सामने आया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा के बीच में ही दंगाई कुछ बड़ा करना चाहते थे ताकि संदेश दूर तक जाए। उन्होंने वही किया भी।

इसलिए ऐसे सुनियोजित दंगों या हिंसा को देखते समय सिर्फ वह नहीं देखा जाता जो सामने दिखाया जाता है। इसके पीछे एक लंबी तैयारी होती है। लोगों को सामूहिक रूप से तैयार करना होता है और धनबल भी खर्च होता है। इसलिए अब्दुल मलिक के बगीचे में किसी मदरसे पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की प्रतिक्रिया में इतनी व्यापक हिंसा हुई इसे स्वीकार कर पाना कठिन है। ऐसा लगता है कि इधर प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता को कैबिनेट में पास करके उसे विधानसभा में पास करने में व्यस्त थी और उधर दंगाई चुपचाप अपनी तरह से हिंसक जवाब देने की तैयारी कर रहे थे। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई एक ट्रिगर प्वाइंट बन गया और दंगाइयों ने रातोंरात वह सब कर दिया जिसके लिए उनकी सामूहिक तैयारी थी। इस हिंसा में पुरुषों के अलावा मुस्लिम स्त्रियों का भी व्यापक स्तर पर शामिल होना संदेह पैदा करता है। बहरहाल, अब राज्य प्रशासन द्वारा इसकी व्यापक जांच में ही सच्चाई सामने आयेगी कि इतनी व्यापक हिंसा का असल उद्देश्य क्या था। लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकार को हल्द्वानी के साथ हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में भी चौकसी और छानबीन बढ़ानी होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि कल किसी न किसी बहाने से ये दोनों जिले भी दंगों की चपेट में ला दिये जाएं। आखिरकार उत्तराखंड की 90 फीसदी मुस्लिम जनसंख्या तो इन्हीं तीन जिलों में रहती है। खासकर हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में जहां मुस्लिम चरममपंथियों का जबर्दस्त प्रभाव है। अगर प्रदेश में शांति और व्यवस्था को बनाकर रखना है तो प्रदेश सरकार को अतिरिक्त सक्रियता दिखानी ही होगी, नहीं तो हिंसक उपद्रवी हावी होते जायेंगे।

सरकार पर हावी रहेगी पाकिस्तानी सेना

डॉ धनंजय त्रिपाठी

बड़े पैमाने पर हिंसा और भरोसे की कमी के बीच पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और चार प्रांतीय असेंबलियों के लिए मतदान हुआ है। मतदान के दौरान समूचे देश में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद रखा गया है। जैसा कि पहले से आशंका जतायी जा रही है, इस चुनाव और इसके नतीजों को संदेह की नजर से देखा जायेगा। इस माहौल में यही लग रहा है कि नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) पहले स्थान पर रहेगी, लेकिन शायद उन्हें बहुमत जुटाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का समर्थन लेना होगा। आखिर इमरान खान को सत्ता से हटाने और उन्हें एवं उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कई नेताओं को चुनाव से अलग रखने में दोनों पार्टियों की भूमिका रही है। ऐसी संभावना बन रही है कि नवाज शरीफ चौथी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रहेंगे। उनकी राह में कोई बड़ी बाधा भी नहीं है क्योंकि उनके ऊपर लगे आरोपों को वापस ले लिया गया है। चुनाव आयोग ने इमरान खान की पार्टी को लड़ने से रोक दिया है और उसके चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। सो, उनके उम्मीदवारों को निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है। जिस प्रकार इमरान खान को रोकने की कवायद राजनीतिक रूप से तथा अदालत और सेना के द्वारा हुई है, उससे यही लगता है कि इमरान के समर्थक कोई उल्लेखनीय जीत हासिल नहीं कर पायेंगे। असल में इस चुनाव का मकसद ही है इमरान खान को पाकिस्तान की राजनीति से बाहर कर देना। इस चुनाव ने फिर यह साबित किया है कि अगर पाकिस्तान में किसी भी प्रकार का लोकतंत्र चलाना है, तो वह पाकिस्तानी सेना को विश्वास में लिये बिना नहीं किया जा सकता है। इमरान खान के साथ जो भी हुआ है और हो रहा है, उसकी एकमात्र वजह उनका सेना से टकराव रहा है। जैसा कि बहुत समय से कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को लंदन निर्वासन से वापस बुलाया ही गया है उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसीलिए उनके खिलाफ सारे मुकदमों को हटा लिया गया है। इसलिए भी लगता है कि पाकिस्तान की आगामी सरकार मिली-जुली सरकार होगी और बिलावल भुट्टो को सरकार से बाहर रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बहरहाल, जो लोग भी पाकिस्तान की राजनीति को समझते हैं, उन्हें इस चुनाव से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। लेकिन कम से कम यह संतोषजनक माना जा सकता है कि वहां सेना का सीधा शासन न होकर एक सरकार के हाथ में सत्ता की बागडोर होगी। पर साथ में यह भी रेखांकित करना जरूरी है कि बहुत से पाकिस्तानी नागरिकों तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर में पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था की साख नहीं बढ़ेगी। नवाज शरीफ पुराने नेता हैं और वे पहले तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दक्षिण एशिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में नेताओं के साथ उनके संबंध हैं। ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान की अगली सरकार इस क्षेत्र में अपनी भूमिका की समीक्षा करेगी और उसमें ठोस सुधार की कोशिश करेगी। तीन अहम पड़ोसी देशों- भारत, ईरान और अफगानिस्तान- के साथ पाकिस्तान के संबंध बेहद खराब हैं। यह स्थिति इस क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। नवाज शरीफ के सामने यह एक बड़ी चुनौती होगी। पड़ोसी देशों के साथ खराब संबंध पाकिस्तान के लिए भी हितकर नहीं हैं। देश की राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रिया में नागरिकों के एक बड़े हिस्से का भरोसा नहीं होना, कई क्षेत्रों में आतंकवाद और अलगाववाद की मौजूदगी तथा राजनीतिक टकराव जैसे गंभीर मुद्दों पर अगर पाकिस्तान की अगली सरकार को सकारात्मक पहल करनी है, तो उसे पड़ोसी देशों के साथ ठीक से रहना होगा। आज पाकिस्तान के सामने अर्थव्यवस्था की बदहाली सबसे बड़ी समस्या है। उसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और दूसरे देशों की मदद से अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना पड़ रहा है। यदि अगली सरकार आर्थिक स्थिति में सुधार करने में असफल रहेगी, तो उसके लिए सत्ता में बने रहना बेहद मुश्किल हो जायेगा। तमाम कमियों के बावजूद नवाज शरीफ एक अनुभवी राजनेता हैं। वैसा अनुभव और संपर्क न तो इमरान खान में था और न बिलावल भुट्टो में है। इसलिए घरेलू और क्षेत्रीय स्तर पर हालात में कुछ सुधार की उम्मीद की जा सकती है।

हाशिये पर रहे लोगों को हक दिलाने वाले चौधरी

केसी त्यागी और बिशन नेहवाल

चौधरी चरण सिंह...किसान मसीहा और भारत रत्न के सच्चे हकदार। ऐसा राजनेता, जिनकी विरासत राजनीतिक क्षेत्र से भी परे फैली हुई है...जिन्हें अद्वितीय नेतृत्व, कृषि क्षेत्र में क्रांति और सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए जाना जाता है। गाजियाबाद में जन्मे चौधरी चरण सिंह का अद्वितीय योगदान उनकी विरासत का आधार है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने परिवर्तनकारी नीतियां बनाईं। किसानों को उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित कराने के लिए कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की। इसके माध्यम से सुगम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तंत्र की शुरूआत हुई, जो उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है। उन्होंने किसानों को न सिर्फ उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाया, बल्कि बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाया और निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया। उनकी दूरदर्शी नीतियों ने किसानों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाया। कृषि स्थिरता को बढ़ावा दिया और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाया। एक आत्मनिर्भर और सशक्त कृषक समुदाय की नींव रखी। कृषि परिदृश्य से परे, चौधरी चरण सिंह सामाजिक न्याय के अग्रज के रूप में उभरे। पेशे से वकील थे और उन्हीं मुकदमों को स्वीकार करते थे, जिनमें मुवक्किल का पक्ष न्यायपूर्ण होता था। व्यापक भूमि सुधारों के लिए उन्होंने सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कायम रखने वाली जमी हुई सामंती संरचनाओं को खत्म करने पर जोर दिया। संसाधनों के अधिक न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देते हुए, समाज के हाशिये पर पड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान की मांग की। समतावादी सिद्धांतों में दृढ़ता से विश्वास करते थे। दलित और हाशिये पर मौजूद वर्गों के अधिकारों की वकालत करते थे। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल, भले ही अल्पकालिक था, मगर नैतिक शासन और सामाजिक समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता अटूट थी। जब वह गृहमंत्री बने, तो मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वित्त मंत्री और उपप्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की। स्थानीय शासी निकायों को शक्ति हस्तांतरित करने वाली पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत, प्राधिकरण के विकेंद्रीकरण में एक मास्टरस्ट्रोक थी। इस कदम ने जमीनी स्तर के लोकतंत्र को सशक्त बनाया, ग्रामीण आबादी को आवाज दी और समावेशी विकास को बढ़ावा दिया। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण तक फैली हुई है, जो ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और समान अवसर बनाने की एक रणनीतिक पहल है।

देश की सुरक्षा और विदेश नीति में स्पष्टता आयी है

अनिल त्रिगुणायत

भारत हो या कोई अन्य देश, अपनी राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा तथा देश का विकास सुनिश्चित करना सरकारों की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। इसे समुचित ढंग से निभाने में विदेश नीति की बड़ी भूमिका होती है। अच्छी विदेश नीति का अर्थ है कि ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बने। इसी की अभिव्यक्ति गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान में हुई है कि भारत दुनिया में सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने की चाह रखता है, लेकिन अपनी सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि देश की सुरक्षा नीति और विदेश नीति में सामंजस्य और स्पष्टता है। पहले यह होता था कि विदेश नीति की बागडोर मुख्य रूप से विशेषज्ञों और कूटनीतिकों के हाथ में हुआ करती थी। वर्तमान सरकार में हमने देखा है कि प्रक्रिया बदली है और विदेश नीति में अधिक जन-भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। देश के लोगों को सरकार अपने निर्णयों के बारे में बताने का प्रयास करती है कि किन आधारों पर और किन कारणों से निर्णय लिये गये हैं। ऐसा हर क्षेत्र में नीतिगत पहल के साथ किया जा रहा है। ऐसे व्यवहार से लोगों का साथ और समर्थन

मिलता है, नीतियां सफल होती हैं तथा देश के विकास की गति बढ़ती है।

गृह मंत्री अमित शाह ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट का विमोचन किया है, जिसमें सर्वे के आधार पर बताया गया है कि शहरी क्षेत्र के 83 प्रतिशत युवा देश की विदेश नीति का समर्थन करते हैं। अमित शाह ने सही कहा है कि यह समर्थन अनेक कारणों से है, जिनमें जी-20 शिखर सम्मेलन में दिल्ली घोषणा को सबकी सहमति के साथ पारित कराना और कोरोना महामारी से पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने में भारत की कोशिशें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हमारे देश के लिए तीन चीजें सबसे अहम हैं। अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आज हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं तथा सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर हम पांचवें स्थान पर हैं। सात प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर है। हमारी मित्रता सबसे अधिक देशों के साथ है। पड़ोसी देशों- चीन और पाकिस्तान- की चुनौती का भी सामना कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि रक्षा तैयारी अच्छी रहनी चाहिए। भारत की यह नीति हमेशा से रही है कि हम किसी अन्य देश की जमीन नहीं चाहते हैं, पर अपने को सुरक्षित रखना है। इसके लिए सैन्य और तकनीकी रूप से हमें सक्षम होना होगा। जैसा कि गृह मंत्री ने रेखांकित किया है, सीमावर्ती क्षेत्रों में पिछले वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है।

तीसरी बात है कि भारत ने सभी देशों, चाहे वह अमेरिका हो, रूस हो, यूरोपीय देश हों, के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर किया है। इन कारकों की वजह से वैश्विक मंचों पर भारत को सम्मान की नजर से देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य प्रमुख नेताओं ने हमेशा वैश्विक सहयोग और वाणिज्य बढ़ाने की पैरोकारी की है। भारत ने जी-20 में वसुधैव कुटुंबकम को आदर्श वाक्य बनाया था। कोरोना महामारी के समय भारत ने दूसरे देशों को टीके उपलब्ध कराने के लिए वैक्सीन मैत्री अभियान चलाया था। भारत की अगुवाई में वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ के दो सम्मेलन हुए हैं, जिनमें 125 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया। जी-20 में भारत की पहल पर अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है। भारत की ही पहल पर प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देशों का एक समूह स्थापित किया गया है। इन प्रयासों से यह स्पष्ट रूप से इंगित होता है कि भारत विकासशील देशों के हित और विकास को प्राथमिकता देता है। जी-20 सम्मेलन में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा बनाने की महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी।

जलवायु परिवर्तन के मसला हो या विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुद्दे हों, भारत ने व्यापक सहभागिता पर बल दिया है। नीतिगत सामंजस्य और स्पष्टता का ही परिणाम है कि जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा की घटनाओं में बड़ी कमी आयी है। गृह मंत्री ने आंकड़ों के हवाले से कहा है कि 2004-14 की अवधि में हिंसा की 33 हजार घटनाएं हुई थीं। साल 2014-23 की अवधि में इनमें 62 प्रतिशत की कमी आयी। इन वर्षों में हिंसा की 12,666 घटनाएं हुईं। हिंसक घटनाओं में ऐसी कमी आने से सुरक्षाकर्मियों और नागरिकों की मौत में भी भारी कमी आयी है। जैसा पहले कहा गया है, सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने से सीमा सुरक्षा बढ़ी है। साथ ही, आतंकी और अलगाववादी तत्वों को नियंत्रित रखने में मदद मिली है। इस विकास से स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत मिली है।

मोदी ने अबकी बार 400 पार की बात यूँ ही नहीं कही है, इसके पीछे पूरा चुनावी गणित है

ललित गर्ग

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा के समय विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मविश्वास एवं कर्मठता से भरकर कहा कि मैं ऐसे आँकड़ों में नहीं पड़ता लेकिन मैं देख रहा हूं कि देश का मिजाज भारतीय जनता पार्टी को 370 और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 400 से ज्यादा सीटें पार करवाकर रहेगा। भाजपा इस बार चुनावों में 400 पार का नारा दे रही है। 2019 चुनावों में भाजपा ने 303 सीटें जीती थीं। निश्चित ही इतने बड़े आंकडे की घोषणा करने के पीछे नरेन्द्र मोदी की सकारात्मक सोच, विकास की राजनीति एवं राष्ट्र-विकास का संकल्प है, वहीं विपक्ष एवं कांग्रेस की नकारात्मक सोच, विरोध के लिए विरोध और विभाजनकारी रवैया उसके लगातार कमजोर होने के कारण हैं। प्रधानमंत्री ने सीटों का जो आकलन किया है, वह सिर्फ इस बात का संकेत है कि भाजपा अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। उन्होंने उन अटकलों पर भी विराम लगा दिया, जिनमें कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के रूप एकजुट हुआ विपक्ष उनको चुनौती देगा, क्योंकि विपक्षी एकजुटता बिखर चुकी है।

मोदी ने संसद के भीतर जब अपने चुनावी लक्ष्य की बात कही तो इसने भाजपा कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से भर दिया, वहीं विपक्ष के सामने आत्मचिन्तन का अवसर प्रदत्त किया। कांग्रेस को 10 साल के दौरान अच्छा विपक्ष बनने का मौका मिला लेकिन इसमें वह पूरी तरह विफल रही। स्वयं तो विफल रही ही, बल्कि विपक्ष में भी कुछ होनहार लोगों को उभरने नहीं दिया। कांग्रेस की नकारात्मक एवं संकीर्ण राष्ट्र-विरोधी राजनीति को देश की जनता महसूस करने लगी है। कांग्रेस किस तरह नकारात्मक राजनीति का शिकार है यह लोकसभा में ही तब देखने को मिला जब सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चैधरी ने बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए। ध्यान रहे कि ऐसे ही सवाल पाकिस्तान खड़े करता रहा है। आखिर उन्हें पाकिस्तान के स्वरों में स्वर मिलाने एवं उसको रास आने वाला बयान देने की जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, वह बार-बार कभी पाकिस्तान तो कभी चीन की तरफदारी करती रही है। मोदी विरोध के नाम पर वह राष्ट्र-विरोध पर उतरती रही है।

प्रधानमंत्री मोदी के इस विश्वास एवं दृढ़ता की अनेक वजहें हैं। एक बड़ी वजह हाल ही में साल 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की शानदार जीत दर्ज करना भी है। विशेषकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का परिणाम तो कल्पना से भी बाहर था। दूसरी वजह, रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा ने लोगों में एक नए जोश का संचार किया है। अंतरिम बजट में ही जिस तरह से आने वाले कुछ महीनों को लेकर नीतियों का एलान किया गया है, वह संकेत है कि भाजपा अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक एवं चमत्कारी जीत की संभावनाओं की और भी वजहें हैं, जिनमें प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सुखद एवं उपलब्धिभरी प्रतिध्वनियां हैं, जैसे चांद एवं सूर्य पर विजय पताका फहरा देने के बाद धरती को स्वर्ग बनाने की मुहीम चल रही है, राष्ट्रीय जीवन में विकास की नयी गाथाएं लिखते हुए भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने की ओर अग्रसर करना है। भारत अब विश्व-गुरु भी बनने की ओर गतिशील है। गत वर्ष 9 एवं 10 सितम्बर को जी-20 देशों का महासम्मेलन भारत में सफलतापूर्वक सम्पन्न होना भी भारत की विश्व स्तर पर मजबूत होने की स्थिति

को दर्शा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस जिम्मेदारी को संभालने का अर्थ था भारत को सशक्त करने के साथ-साथ दुनिया को एक नया चिन्तन, नया आर्थिक धरातल, शांति एवं सह-जीवन की संभावनाओं को बल देना। नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता धीरे-धीरे सामने आने लगी है एवं उसके उद्देश्यों की परते खुलने लगी है। भाजपा इसलिए भी आशान्वित है, क्योंकि जिस विपक्षी एकता की बात 2023 के मध्य से चल रही थी, उसमें दरारे पड़ती ही जा रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां अपने-अपने ढंग से चुनाव लड़ने को तैयार हैं और कांग्रेस से उनकी खींचतान चल रही है। फिर, जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थीं, वहां पार्टी ने अपने अनवरत प्रयासों से खुद को मजबूत बना लिया है, फिर चाहे वह महाराष्ट्र हो या बिहार।

कांग्रेस एवं विपक्षी दलों के पास भाजपा एवं मोदी विरोध का कोई सशक्त धरातल एवं मुद्दें नहीं है। वैसे तो हर एक का जीवन अनेकों विरोधाभासों एवं विसंगतियों से भरा रहता है। लेकिन कांग्रेस का हर दिन कई विरोधाभासों के बीच बीत रहा है। कांग्रेस की उल्टी गिनतियां चल रही हैं। उसकी उल्टी गिनती तो लम्बी चलेगी। पर जनता के दिमाग में एक बात गहरे तक बैठी हुई है कि मोदी के नेतृत्व में सब कुछ बदल जाएगा, भारत सशक्त हो जायेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा एवं सब कुछ श्रेष्ठ हो जाएगा। इसके विपरीत कांग्रेस की जनता पर पकड़ ढ़िली पड़ती जा रही है, उसके बयानों में कोई बुनियादी मुद्दें नहीं होते, बार-बार बेरोजगारी की चर्चा सुनने को मिलती है, जबकि 2014 से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट केवल 12 लाख करोड़ के आसपास था। बीते 10 सालों में बजट बढ़कर 44 लाख करोड़ हो गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में कितनी नौकरियां पैदा हुई होंगी। आज युवाओं के लिए जितने नए अवसर बने हैं, ये पहले कभी नहीं बने। आज चारों तरफ स्टार्टअप्स की गूंज है, यूनिकॉर्न्स चर्चा में है। 2014 के पहले डिजिटल इकोनॉमी का साइज ना के बराबर था। आज भारत, दुनिया की अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी है। लाखों युवा इससे जुड़े हैं और उनके सपनों को पंख लगे हैं। इसी तरह महिलाओं को सम्मानजनक जिन्दगी देने एवं उनके विकास को अग्रसर करने में मोदी सरकार ने व्यापक प्रयत्न किये हैं। एक संकल्प लाखों संकल्पों का उजाला बांट सकता है यदि दृढ़-संकल्प लेने का साहसिक प्रयत्न कोई शुरू करे। निश्चित ही अंधेरों, अवरोधों एवं अक्षमताओं से संघर्ष करने की एक सार्थक मुहिम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में शुरू हुई थी और उनका तीसरा कार्यकाल इन दृष्टियों से ऐतिहासिक होगा, यह आम जनता में पनप रहा विश्वास है।

मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल में जता दिया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति वाली सरकार अपने फैसलों से कैसे देश की दशा-दिशा बदल सकती है। कैसे राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए पड़ोसी देशों को चेता सकती है, कैसे स्व-संस्कृति एवं मूल्यों को बल दिया जा सकता है। काशी हो या अयोध्या या ऐसे ही धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रांति के परिदृश्य- ये अजूबे एवं चैंकाने वाले लगते हैं। अयोध्या से नरेन्द्र मोदी ने जो संदेश दिया है, उसे केवल चुनावी नफा-नुकसान के नजरिये से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक सशक्त होते राष्ट्र के नजरिये से देखा जाना चाहिए। उनका यह कहना खास मायने रखता है कि सदियों की गुलामी के चलते भारत को जिस हीनभावना से भर दिया गया था, आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। यह स्थिति आगामी लोकसभा चुनाव की जमीन बनेगी। स्पष्ट है, आम चुनाव में अब बहुत दिन शेष नहीं है, और दोनों मोर्चों की बिसात कमोबेश बिछ चुकी है। हालांकि, एक तरफ भाजपा जैसा सुगठित दल हैं, जिसके पास मोदी जैसा एक मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट नजरिया है। जबकि उसे चुनौती देने वाले मोर्चे में फिलहाल काफी उथल-पुथल है। ऐसे में, यदि विरोधी खेमा नहीं चेता, तो प्रधानमंत्री ने जिन आंकड़ों के साथ जीत का दावा किया, वह यदि सच हो जाए, तो आश्चर्य नहीं होगा।

प्रधानमंत्री पिछले 10 वर्षों के दौरान हासिल अपनी सरकार की उपलब्धियां न गिनाकर, विपक्ष और खासकर कांग्रेस पर तंज के तीर बरसाए, इसके पीछे उनका स्पष्ट राजनीति मकसद रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यह बखूबी जानते हैं कि अपने प्रतिपक्षी को कभी कमतर नहीं आंकना चाहिए, फिर अगले लोकसभा चुनाव के महासंग्राम में जिस पार्टी से उनका सबसे अधिक सीटों पर आमना-सामना होना है, उसकी कमियों, उसके अंतर्विरोधों, उसकी नाकामयाबियों एवं नकारात्मक सोच को देश की जनता के सामने रखना अधिक प्रभावी एवं मनोवैज्ञानिक तरीका है, उस पर दबाव बनाने एवं उसे कमजोर साबित करने का। मोदी इसमें माहिर है एवं राजनीतिक परिवक्रता से भरे हैं।

कागज-2 सतीश कौशिक ने अपनी आखिरी फिल्म में उठाए अहम सवाल

दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक की आखिरी फिल्म 'कागज 2' 1 मार्च 2024 को रिलीज होगी। शुक्रवार को मेकर्स ने इसका ट्रेलर जारी किया। यह फिल्म जीवन के अधिकार, स्वतंत्र आवाजाही के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए एक आम आदमी की लड़ाई के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में सतीश कौशिक के दोस्त और दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर भी अहम भूमिका में हैं। 'कागज 2' का ट्रेलर 9 फरवरी को रिलीज़ हुआ। फिल्म की पहली किस्त में पंकज त्रिपाठी मुख्य भूमिका में थे। बताया जा रहा है कि 'कागज 2' वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है और इसमें अनुपम खेर, सतीश कौशिक, दर्शन कुमार, नीना गुप्ता और स्मृति कालरा महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। अनजान लोगों के लिए, वकील साधोराम केवट की भूमिका में सतीश कौशिक भी पहली किस्त का हिस्सा थे। वीके प्रकाश द्वारा निर्देशित और शशि सतीश कौशिक, रतन जैन और गणेश जैन द्वारा निर्मित, यह फिल्म सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट एलएलपी और वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का संयुक्त निर्माण है। वीनस फिल्म्स के निर्माता रतन जैन ने कहा, सतीश जी के साथ मेरा जुड़ाव बहुत पुराना है। उन्होंने मेरी कंपनी के लिए एक फिल्म का निर्देशन किया और हमने साथ में कई फिल्मों का निर्माण किया। 'कागज 2' उनके दिल में एक विशेष स्थान रखती है। यह है मेरे प्रिय मित्र को श्रद्धांजलि।

उन्होंने आगे कहा, फिल्म का अनोखा विक्रय बिंदु संदेश में निहित है- अपना रास्ता बनाने के लिए दूसरों का रास्ता अवरुद्ध न करें। राजनीतिक रैलियां और विरोध प्रदर्शन अक्सर ट्रैफिक जाम का कारण बनते हैं, जिससे आम लोगों को असुविधा होती है।

जब बेटे ऋषि को लेकर होटल रहने चली गई थीं कृष्णा कपूर

ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में अपने और अपनी फैमिली के बारे में बहुत सी बातों का खुलासा किया था. उन्होंने नरगिस और वैजयंतीमाला के साथ अपने पिता के रिलेशन के बारे में भी लिखा था. इसमें उन्होंने लिखा कि उनके पिता राज कपूर के नरगिस के साथ संबंध थे, दोनों के संबंधों के बारे में परिवार को पता था और इसके बाद भी घर में कुछ नहीं बदला. हालांकि वैजयंतीमाला की बात आई तो उनकी मां कृष्णा राज कपूर ने विरोध करना शुरू कर दिया. ऋषि कपूर लिखते हैं, मैं बहुत छोटा था, जब मेरे पिता का नरगिस जी के साथ अफेयर था. इसलिए मैं उनके रिश्ते से प्रभावित नहीं हुआ. मुझे याद नहीं है कि घर में इस कारण से कुछ हुआ हो, लेकिन मुझे याद है कि जब पापा वैजयंतीमाला से जुड़े थे, तो मेरी मां ने विरोध किया और हम मरीन ड्राइव के नटराज होटल में रहे और वहां से हम दो महीने के लिए चित्रकूट के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए. मेरी मां ने तब तक हार नहीं मानी, जब तक कि उसने अपने जीवन के उस अध्याय को समाप्त नहीं कर दिया हालांकि बाद में वैजयंतीमाला ने इस अफेयर को फिल्म प्रमोशन के लिए एक चाल बताया था. ऋषि लिखते हैं कि कुछ साल पहले प्रकाशित एक इंटरव्यू में वैजयंतीमाला ने मेरे पिता के साथ कभी संबंध होने से इनकार किया. उन्होंने दावा किया पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया गया. मैं भड़क गया था. दिखाओ कि अफेयर कभी नहीं हुआ? उन्हें तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वह अब सच्चाई बयां करने के लिए मौजूद नहीं हैं.

सेम टू सेम माधुरी लगती है ये लड़की, मच गया सोशल मीडिया पर हंगामा

बॉलीवुड में आज भी माधुरी दीक्षित का कोई जवाब नहीं है. माधुरी की हर अदा और हर अंदाज के लोग दीवाने हैं. डांस के मामले में तो कोई भी उनकी बराबरी करने वाला नहीं है. उनकी पॉपुलैरिटी का ही असर है कि उनके जैसे दिखने वाले लोग भी पॉपुलर हो रहे हैं. माधुरी दीक्षित की एक हमशक्ल या डॉपलगैंगर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देख पहली नजर में तो सच में पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये असली माधुरी नहीं हैं. इंस्टाग्राम पर शेयर हुए वीडियो में माधुरी जैसी दिखने वाली मधु, लाल और गोल्डन साड़ी में दुल्हन के जैसे गहना पहने और मेकअप में माधुरी दीक्षित के गाने पर उनकी तरह एक्सप्रेशन्स देती नजर आ रही हैं. वीडियो में दिख रहीं महिला सच में बिल्कुल माधुरी दीक्षित की तरह नजर आ रही हैं. साजन-साजन तेरी दुल्हन गाने पर माधुरी की हमशक्ल बिल्कुल माधुरी की तरह नजर आ रही हैं. साइड से मधु को देखने पर आप भी एक बार चकरा जाएंगे. हुबहू माधुरी सी दिखने वाली मधु उनकी बहुत बड़ी फैन हैं. मधु का इंस्टाग्राम प्रोफाइल इस तरह के वीडियोज से भरा पड़ा है. माधुरी की हमशक्ल के इस वीडियो पर कमेंट करते हुए यूजर्स उनकी तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, आप एक दम माधुरी दिखती हो. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, एक दम सेम माधुरी जी. जबकि एक यूजर ने लिखा, कार्बन कॉपी हैं आप. वहं दूसरे यूजर ने लिखा, कोयला फिल्म की माधुरी लग रही हैं.

सलमान व सूरज के साथ प्लान कर रहे हैं बिग स्कैल फ़िल्म

सबसे बड़ी और सबसे सफल डायरेक्टर-एक्टर जोड़ी सूरज बड़जात्या और सलमान खान ने अब तक कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं । इसमें मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन..!, और प्रेम रतन धन पायो शामिल है । ऐसे में सलमान खान और सूरज बड़जात्या का साथ में अगले सहयोग का हमेशा लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है । हालांकि पिछले साल, इस जोड़ी ने कन्फर्म किया था कि वे प्रेम रतन धन पायो (2015) के आठ साल बाद अपने पांचवें सहयोग के लिए फिर से साथ आ रहे हैं, और उनकी अपकमिंग परियोजना बड़े पैमाने पर बनाई जाने वाली है ।

शाहरुख खान के डायरेक्टर ने जब प्रीति जिंटा से कहा था मुंह धोकर आओ, एक्ट्रेस ने 26 साल बाद खोला राज

प्रीति जिंटा बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, जिन्हें कोई मिल गया, दिल है तुम्हारा, कभी अलविदा ना कहना और वीर जारा जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए जाना जाता है. उनकी खूबसूरती के साथ साथ एक्टिंग दर्शकों के दिलों पर राज करती है. वहीं फैंस उनके कमबैक का इंतजार बेसब्री से करते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म दिल से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है, जो चर्चा में आ गया है. ट्विटर पर प्रीति जिंटा ने लिखा, ये तस्वीर फिल्म दिल से के सेट पर पहले दिन ली गई थी. मैं मणिरत्नम सर और शाहरुख खान के साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी. जब मणि सर ने मुझे देखा तो वे मुस्कुराए और विनम्रता से मुझे अपना चेहरा धोने के लिए कहाज लेकिन सर... मेरा मेकअप उतर जाएगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा.... मैं बिल्कुल यही चाहता हूं... कृपया अपना चेहरा धो लें. फिल्म की बात करें तो 1998 में आई दिल से डायरेक्टर मणि रत्नम की फिल्म है, जिसमें प्रीति जिंटा और शाहरुख खान के अलावा मनीषा कोइराला, मलाइका अरोड़ा, जोहरा सहगल और संजय मिश्रा अहम किरदार में नजर आए थे. इस फिल्म के गाने जहां आज भी फैंस के बीच फेमस हैं. वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अच्छी कमाई हासिल की थी.

प्यार भरे सप्ताह में बिखरेंगी खुशियाँ!

प्यार के इस हफ्ते में, एण्डटीवी की कहानियां दर्शकों चहेरे पर मुस्कान बिखेरने के लिये तैयार हैं। 'हप्पू की उलटन पलटन' में दरोगा हप्पू सिंह को वैलेंटाइन्स डे पर दोस्ती की असली अहमियत पता चलेगी। वहीं, 'भाबीजी घर पर हैं' में तिवारी और विभूति अपनी-अपनी भाबियों के साथ वैलेंटाइन्स डे का जश्न मनाने के लिये अपने सारे तिकड़म भिड़ायेंगे।

एण्डटीवी के 'हप्पू की उलटन पलटन' की कहानी के बारे में बताते हुये दरोगा हप्पू सिंह ने कहा, ''राजेश (गीतांजलि मिश्रा) और बिमलेश (सपना सिकरवार) वैलेंटाइन डे मनाने के लिये अपने पतियों को एक होटल में टेबल रिजर्व करने के लिये कहती हैं, जिसकी कीमत 21,000 रूपये है। दूसरी ओर, कमलेश (संजय चैधरी) केट (गजल सूद) से शादी के बाद एक स्पेशल वैलेंटाइन्स डे सेलीब्रेट करने का वादा करता है। हप्पू (योगेश त्रिपाठी) टेबल रिजर्व कराने के लिये मनोहर (नितिन जाधव) को पैसे देता है। हालांकि, बेनी (विश्वनाथ चटर्जी) पैसों की तंगी से जूझ रहा है और टेबल रिजर्व नहीं करा पा रहा है, इसलिये कमिश्नर (किशोर भानुशाली) से पैसे मांगता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। हप्पू को जब यह पता चलता है, तो वह बेनी को उसके पास नहीं आने के लिये डांट लगाता है। जब बिमलेश फिर से टेबल रिजर्व कराने पर जोर देती है, तो बेनी मदद मांगने हप्पू के पास जाता है। हप्पू उसे एक शर्त पर पैसे उधार देने के लिये तैयार होता है, वह यह है कि जब वह बेनी को पैसे देगा, तो उसका वीडियो बनायेगा। यह सुनकर बेनी अपमानित एवं निराश महसूस करता है। इसलिये वैलेंटाइंस डे के दिन बेनी और बिमलेश घर पर ही रहते हैं, जबकि हप्पू और राजेश होटल में सेलीब्रेट करते हैं। घर लौटते समय बेनी एक अनजान व्यक्ति से टकराता है, जिसका नाम नायर है। नायक को सहायता चाहिये होती है और बेनी उसकी मदद करता है। बेनी के व्यवहार से खुश होकर वह उसे चेन्नई में एक जॉब ऑफर करता है। बेनी बहुत खुश होता है और अपनी नई

नौकरी एवं दूसरे शहर में शिफ्ट होने के बारे में सबको बताता है। दूसरी ओर, हप्पू मनोहर से कहता है कि यदि बेनी दूसरे शहर चला जाता है, तब भी वे एक साथ पार्टी करते रहेंगे। लेकिन हप्पू को जल्द ही बेनी की कमी खलने लगती है और वह उदास हो जाता है। इसी तरह राजेश को भी बिमलेश की कमी महसूस होने लगती है, जो पैकिंग करने में व्यस्त है और उस पर ध्यान एवं समय नहीं दे पा रही है। कटोरी अम्मा (हिमानी शिवपुरी), राजेश, हप्पू और ऋतिक (आर्यन प्रजापति), चमची (ज़ारा वारसी) और रणबीर (सोमया आज़ाद) उन दोनों को साथ में रहने के लिये मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अभी से ही महसूस होने लगता है कि वे उन्हें कितना मिस करने वाले हैं। लेकिन बेनी अपने फैसले पर अड़ा रहता है, जिससे हप्पू बेनी के खिलाफ नायर को भड़काने के लिये मजबूर हो जाता है।''

एण्डटीवी के 'भाबीजी घर पर हैं' की कहानी के बारे में बताते हुये अंगूरी भाबी कहती हैं, ''विभूति (आसिफ शेख) दिन में सपना देखता है कि वह अंगूरी (शुभांगी अत्रे) के साथ वैलेंटाइन्स डे मना रहा है। सपने में अंगूरी उससे अपने प्यार का इजहार करती है। हालांकि, असली में जब वह अंगूरी से मिलता है, तो उससे वैलेंटाइन्स डे के प्लान के बारे में पूछता है। वह चाहती है कि लड्डू के भैया (रोहिताश्व गौड़) उसे कुल्लू मनाली घुमाने ले जाए। अंगूरी के प्लान को बिगाड़ने और खुद ही उसके साथ दिन गुजारने की सोचकर विभूति एक योजना बनाता है। इस बीच तिवारी अनीता (विदिशा श्रीवास्तव) से मिलकर वैलेंटाइन्स डे का प्लान पूछता है। अनीता को लगता है कि विभूति के पास उसके लिये कुछ प्लान है। लेकिन तिवारी उसकी बात को नकार देता है और कहता है कि विभूति को तो यह मौका याद भी नहीं रहता है।

तिवारी की बात से नाराज होकर अनीता उससे एक शर्त लगाती है। जब तिवारी का विभूति से सामना होता है, तब वह एक कहानी गढ़ता है और दावा करता है कि अनीता को वैलेंटाइन्स डे के लिये हीरों का हार चाहिये। यह सुनकर विभूति बड़े तनाव में आ जाता है। तनाव को दूर करने के लिये तिवारी सलाह देता है कि विभूति आने वाले वैलेंटाइन्स डे पर ध्यान न दे। अंगूरी जब तिवारी को कुल्लू मनाली चलने के लिये कहती है, तब वह झूठ कहता है कि उसे बिजनेस में नुकसान हो गया है और इसलिये अंगूरी की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। अंगूरी मार्गदर्शन के लिये डेविड चाचा (अनूप उपाध्याय) के पास जाती है।

डेविड चाचा उसे विंटेज टीवी पर दिखने वाले एक संत के पास जाने के लिये कहता है। इससे रोमांचित होकर अंगूरी तुरंत बात को मान जाती है। संत के भेश में विभूति ही अंगूरी से कहता है कि वह अपने पड़ोसी को अपना वैलेंटाइन बना ले। इससे उसके पति को बिजनेस में हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी। यह बात मानकर अंगूरी विभूति के पास जाती है और डेट के लिये पूछती है। इस बीच तिवारी अनीता को गुमनाम चिट्ठियाँ और तोहफे भेजता है।''

रजनीकांत की लाल सलाम पर भारी साउथ की ईगल

9 फरवरी फिल्मों के लिए काफी धमाकेदार रहा. जहां कुल चार फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इनमें से एक बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर-कृति सेनन के तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और बाकी तीन साउथ की लाल सलाम, अनवेशप्पिन कांडेतम और रवि तेजा की ईगल का नाम शामिल है. लेकिन साउथ की मूवीज में ईगल ने बाजी मारते हुए रजनीकांत और थोविनो थॉमस को भी पीछे छोड़ दिया है. ईगल ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 6.1 करोड़ की कमाई हासिल की है. जबकि लाल सलाम ने केवल 4.3 करोड़ का कलेक्शन अपने नाम किया है. इशके चलते रजनीकांत के स्पेशल कैमियो वाली फिल्म लाल सलाम पर रवि तेजा की ईगल भारी पड़ती हुई नजर आई है. जबकि बॉलीवुड मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की टक्कर ईगल से होती दिख रही है क्योंकि इस फिल्म ने भी 6 करोड़ पार की कमाई अपने नाम की है. ईगल की बात करें तो कार्तिक गट्टामनेनी द्वारा निर्देशित रवि तेजा की फिल्म में अनुपमा परमेशवरर, काव्या थापर, मधू और विनय राय जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. 80 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म की कहानी एक कॉन्ट्रेक्ट किलर सहदेव वर्मा की है, जिसे रचना से प्यार हो जाता है. इसके चलते वह इस दुनिया से अवैध हथियारों को खत्म करने की कोशिश करता है. इसी लड़ाई में उसकी मुलाकात पत्रकार नलिनी राव से होती है, जो कहानी को दिलचस्प मोड़ देती है.

तलाक की अफवाहों के बीच अभिषेक ने की ऐश्वर्या की तारीफ

अभिषेक बच्चन ने हाल ही में अपना 48वां जन्मदिन मनाया और अभिनेता सभी का प्यार पाकर बहुत खुश हैं, लेकिन उन्हें अपना जन्मदिन अपने प्रियजनों, पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन के साथ मनाना पसंद है। हाल ही में बच्चन अपने बीच के झगड़े को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसी भी जोरदार चर्चा थी कि परिवार के प्रति उदासीन विचार रखने के कारण अभिषेक और ऐश्वर्या अलग होने जा रहे हैं। अभिनेता ने हाल ही में अपने साक्षात्कार में अपनी पत्नी के साथ अलगाव की सभी अफवाहों को खारिज करते हुए उन्हें एक शानदार मां बताया। अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी ऐश्वर्या से बहुत प्रभावित हैं और जिस तरह से वह अपनी बेटी आराध्या की देखभाल करती हैं, वह उसे बेहद पसंद करते हैं और उसे अपने ब्रह्मांड का केंद्र कहते हैं। टाइम्स नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, यह आराध्या के लिए है कि यह दिन खास बन जाता है... अगर संभव हो तो मैं अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाना पसंद करता हूं। लेकिन अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं तो यह मेरे लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं होगी। आराध्या हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है। अपने अद्भुत जीवन का श्रेय ऐश्वर्या को देते हुए जूनियर बी ने कहा, एक शानदार मां होने का पूरा श्रेय ऐश्वर्या को जाता है। पिता बनने ने जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया है।

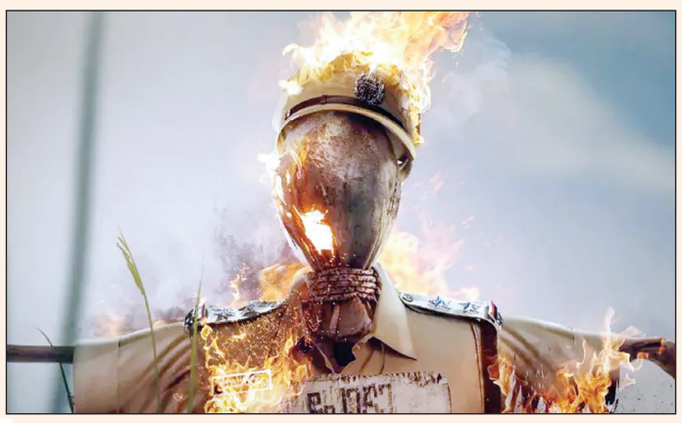

अनवेषीप्पिन कांडेतुम ने सिनेमाघरों में मचाया तहलका

साउथ की फिल्म 2018 तो याद ही होगी, जिसने 12 करोड़ के बजट में 178 करोड़ की कमाई हासिल की थी. वहीं ब्लॉकबस्टर कहलाई थी. वहीं इस फिल्म में टोविनो थॉमस ने साउथ ही नहीं बॉलीवुड फैंस का भी दिल जीत लिया था. इसी बीच 9 फरवरी को वह अपनी नई मूवी अनवेषीप्पिन कांडेतुम के साथ सिनेमाघरों में तहलका मचाने आ गए हैं, जिसका पहले दिन का कलेक्शन सामने आ गया है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकलनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन अनवेषीप्पिन कांडेतुम ने 1.20 करोड़ की ओपनिंग भारत में की है. वहीं वर्ल्डवाइड यह आंकड़ा 2 करोड़ पार हो गया है. हालांकि वीकेंड पर इस फिल्म के आंकड़े बढ़ने के आसार साफ नजर आ रहे हैं. लेकिन लाल सलाम और ईगल की रिलीज के साथ यह फिल्म कितना दर्शकों के बीच अपनी जगह बना पाती है यह देखना दिलचस्प होगा. अनवेषीप्पिन कांडेतुम एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डार्विन कुरियाकोज ने डायरेक्ट किया है. वहीं कहानी जीनी अब्राहम ने लिखी है. जबकि टोविनो थॉमस के साथ सिद्दीकी, शम्मी तिलकन, बाबूराज और इंद्रान्स अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म की कहानी दो बड़े अपराधों के इर्दगिर्द है, जिसके कारण पूरा केरल हैरान रह जाता है. वहीं इसकी जांच पुलिस करती है, जिसमें एसआई के किरदार में टोविनो थॉमस दिख रहे हैं. 8 करोड़ का बजट इस फिल्म का बताया जा रहा है, जो कि एक वीकेंड में फिल्म कमा सकती

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू हो जाएगा सीएए : शाह

नईदिल्ली। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करके सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिकता संसोधन अधिनियम यानी सीएए लागू कर दिया जाएगा। गृह मंत्री ने यह बात एक कार्यक्रम के दौरान कही है। यहां चर्चा कर दें कि अप्रैल और मई महीने में चुनाव होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छिनेगी। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता उपलब्ध कराना है। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि यह वादा मूल रूप से देश की सबसे पुरानी पार्टी ने ही उनसे किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने अनुच्छेद 370 हटाया इसलिए लोग बीजेपी को 370 सीट पर जीत देने का काम इस बार करेंगे।

ईडी ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी को समन भेजा

लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को समन भेजा है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह मामला लुईस खुर्शीद के नेतृत्व वाले एक ट्रस्ट द्वारा कृत्रिम अंगों और उपकरणों के वितरण में सरकारी निधि के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। सूत्रों ने बताया कि उन्हें धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए 15 फरवरी को लखनऊ में ईडी के कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत ने दो दिन पहले इस मामले में लुईस खुर्शीद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तारीख तय की थी। सलमान खुर्शीद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं।

प्रधानमंत्री का कार्यकाल भ्रष्टाचारियों का अमृतकाल

नई दिल्ली। कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ताजा घटनाक्रम में सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान सुरंग परियोजना में कथित खामियों का जिक्र किया है। उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि परियोजना में कथित गंभीर खामियों को लेकर दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने लार्सन एंड टुब्रो को नोटिस जारी किया है। इस मामले में शनिवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म- एक्स पर जारी बयान में राहुल गांधी ने कहा, देश में भ्रष्टाचारियों का अमृतकाल चल रहा है। 777 करोड़ रुपये की लागत से बनी प्रगति मैदान सुरंग केवल एक साल में बेकार हो गई। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर विकास परियोजना पर योजना के बजाय मॉडलिंग कर रहे हैं।

मप्र के एक राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस में उठापटक

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। कमलनाथ ने सोनिया गांधी से खुद के लिए राज्यसभा के टिकट की मांग की है। दरअसल, मध्यप्रदेश से राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। अंकगणित के हिसाब से इनमें से चार भाजपा और एक सीट कांग्रेस को जाएगी। कांग्रेस में इस एक सीट के लिए एक अनार सौ बीमार जैसी स्थिति है। पूर्व सीएम कमलनाथ से लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव तक कई दिग्गजों के नाम इस एक सीट के लिए चल रहे हैं, हालांकि कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग कार्ड के चलते इन नामों में अरुण यादव का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। इस बीच 13 फरवरी को कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों को डिनर पर बुलाया है। अपने बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से लड़ाने का एलान कर चुके कमलनाथ खुद के लिए राज्यसभा चाहते हैं।

छगन भुजबल को मिली धमकी भरी चिट्ठी, बढ़ाई गई सुरक्षा

मुंबई। महाराष्ट्र के खाद्य औरनागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल को एक चिट्ठी मिली, जिसमें उन्हें उनकी जान को खतरा होने के बारे में आगाह किया गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने महाराष्ट्र के मंत्री के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने कहा कि ऐसी कई चिट्ठी मिलने के बाद भी वह अपने विश्वास से पीछे नहीं हटेंगे। भुजबल के नासिक दफ्तर में शुक्रवार को चिट्ठी भेजी गई थी। चिट्ठी के जरिए उन्हें बताया गया कि पांच लोगों को उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए 50 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी। वे लोग मंत्री की तलाश में हैं। अमबद पुलिस ने इसके बाद मंत्री के आवास और दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। नासिक के येओला विधानसभा क्षेत्र के नेता को इससे पहले भी धमकी भरा फोन कॉल और चिट्ठी मिल चुका है। भुजबल ने मीडिया से कहा, मैं अपने विचारों पर अडिग हूं। जितनी भी चिट्ठी मिले, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने विचारों के साथ काम करना जारी रखूंगा।

राज्यसभा में चौधरी चरण सिंह पर उठाया सवाल तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर भड़के सभापति

चौधरी चरण सिंह अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा: धनखड़

नईदिल्ली। राज्यसभा में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा मामले पर गहमागहमी वाला माहौल रहा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा गया कि इस भाषा का प्रयोग न करें। मैं चौधरी चरण सिंह का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। वह बेदाग सार्वजनिक जीवन, बेदाग अखंडता और किसानों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए खड़े हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है।

वहीं, सत्ता पक्ष की ओर से जयंत चौधरी जब अपनी बात रख रहे थे तब कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि उन्हें किस नियम के तहत बोलने का अवसर दिया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि जिन भी शख्सियतों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है उस पर कोई वाद-विवाद नहीं है लेकिन किस नियम के अधीन जयंत चौधरी को बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य नियमों के अधीन भी मुद्दा उठाना चाहते हैं तो उन्हें 'चुप' करा दिया जाता है।

उन्होंने आसन के व्यवहार पर सवाल उठाए, जिस पर सभापति धनखड़ ने गहरी आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे उन्हें बहुत ठेस पहुंची है। सभापति ने सदन को बताया कि जयंत चौधरी ने सुबह उन्हें एक पत्र लिखा था कि वह चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर सदन में 'कुछ' बोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी चरण सिंह के पोते हैं इसलिए उन्होंने उन्हें बोलने का मौका दिया। इस मुद्दे पर सदन में कुछ देर हंगामे का माहौल रहा।

आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला बहुत बड़ा फैसला है। शुक्रवार को इस घोषणा के बाद लोगों ने दिवाली मनाई। शुक्रवार को किसानों ने सीपी में मिठाइयां बांटी। इससे यही पता चलता है कि यह फैसला सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि किसानों को मजबूत करने वाला फैसला है। जयंत चौधरी ने कहा कि सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्षी सदस्यों के 'दुर्व्यवहार' से वह बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा, ''हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठबंधन के बनने और टूटने, चुनाव लड़ने

और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं। लेफ्ट, राइट और सेंटर में ही हम बंटे रहेंगे तो देश के असली धरतीपुत्र का हम सम्मान कैसे रख पाएंगे?'' चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार का आभार जताते हुए जयंत चौधरी ने कहा, ''मैं कहना चाहता हूं कि एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है। ऐसे ही सरकार धरतीपुत्र चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे सकती है।''

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व का क्षण है कि पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर सम्मान दिया...कांग्रेस को आज जश्न मनाना चाहिए था कि उनके पूर्व पीएम को पीएम मोदी ने सम्मानित किया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उनके सरनेम में गांधी नहीं था न नेहरू, गांधी होता तो चल जाता।..वह स्वयं को भारत रत्न देने में लगे हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह,पीवी नरसिम्हा राव गारू और डॉ. एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आज पूरा देश उनका गुणगान कर रहा है लेकिन नेता प्रतिपक्ष को चौधरी चरण सिंह, डॉ. एमएस स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव गारू का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।

जयंत को खरगे ने टोका तो भड़के केंद्रीय मंत्री

राज्यसभा में भारत रत्न से सम्मानित हस्तियों के सम्मान में चर्चा के बीच जब चौधरी चरण सिंह का जिक्र आया और जयंत चौधरी बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया। विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला नाराज हो गए और उन्होंने कांग्रेस को चेताते हुए कहा कि इस देश में किसानों की आवाज रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। दरअसल जयंत चौधरी ने राज्यसभा में बोलना शुरू किया तो कांग्रेस सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानना चाहा कि किस नियम के तहत रालोद नेता को बोलने की अनुमति दी गई है? खरगे ने कहा कि यह गर्व की बात है और हम पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव, चरण सिंह तथा एमएस स्वामीनाथन को सैल्यूट करते हैं। खरगे की आपत्ति पर मछलीपालन, डेयरी और पशुपालन केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा कि सदन में नियमों का पालन होना चाहिए। आज सदन में जब चौधरी चरण को भारत रत्न मिलने पर उनके पोते जयंत चौधरी समेत पूरा सदन बधाई देने के लिए बैठा था, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस दल ने खड़े होकर इसका विरोध क्यों किया? जैसे ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू किया तो परषोत्तम रूपाला ने नाराज होते हुए कहा %सुनो....सुनो...इस देश में किसानों की आवाज को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। नहीं होगा...होगा भी नहीं। आप एक किसान की प्रशंसा नहीं सुन सकते हो। एक किसान को भारत रत्न मिला इसमें कांग्रेस के खेमे में क्यों आग लग गई? रूपाला ने कहा कि जब नेता विपक्ष बोलते हैं तो आप (सभापति) हमें बोलते हैं कि नेता विपक्ष बोल रहे हैं, उनकी बात सुनिए, लेकिन अब वही नेता विपक्ष आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते और वो भी ऐसे मौके पर, जब एक किसान को भारत रत्न देने का फैसला किया गया हो। यही कांग्रेस का चरित्र है।

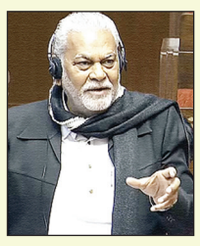

लोकसभा में बोले अमित शाह

भारत की संस्कृति और रामायण को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में शनिवार को नियम 193 के तहत 'ऐतिहासिक श्रीराम मंदिर के निर्माण और श्रीराम लला की प्राण प्रतिष्ठा' विषय पर चर्चा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज किसी का जवाब नहीं दूंगा। मैं मन की बात और जनता के मन की बात देश के सामने रखना चाहता हूं। वह आवाज, जो वर्षों से अदालत के कागजों में दबी हुई थी। 22 जनवरी 2024 के बारे में भले ही कुछ लोग कुछ भी कहें, वह दिन दस सहस्त्र से भी ज्यादा वर्षों के लिए ऐतिहासिक दिन बना रहेगा।

उन्होंने कहा कि 1528 से चल रही संघर्ष और अन्याय के खिलाफ लड़ाई की जीत का दिन है। 22 जनवरी 2024 का दिन समग्र भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण का दिन है। देश की कल्पना राम और राम चरित्र के बगैर नहीं हो सकते। राम और राम का चरित्र भारत के जनमानस का प्राण है। संविधान की पहली प्रति से लेकर महात्मा गांधी के आदर्श भारत की कल्पना तक राम का नाम लिया जाता रहा।

उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति और रामायण को अलग करके देखा ही नहीं गया। कई भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों में रामायण का जिक्र है। कई सारे देशों ने रामायण को स्वीकारा और आदर्श ग्रंथ के रूप में प्रस्थापित किया है। राम और रामायण से अलग देश की कल्पना हो ही नहीं सकती। ये लड़ाई 1528 से लड़ी जा रही थी। दशकों तक लड़ाई चली। तकरीबन 1858 से कानूनी लड़ाई चल रही थी। 330 साल के बाद कानूनी लड़ाई का आज अंत आया है और रामलला अपने गर्भगृह के अंदर विराजमान हैं।

अमित शाह ने कहा कि आंदोलन से अनभिज्ञ होकर इस देश के इतिहास को पढ़ ही नहीं सकता। 1528 से

हर पीढ़ी ने इस आंदोलन को वाचा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में ही यह परवान चढ़ा और स्वप्न सिद्ध हुआ। राम जन्मभूमि का इतिहास लंबा है। राजाओं, संतों, निहंगों और कानून विशेषज्ञों ने इस लड़ाई में अपना योगदान दिया है। इन सभी योद्धाओं का आज हम विनम्रता से स्मरण करना चाहता हूं।

उन्होंने कहा कि गिलहरी की तरह कई लोगों ने अपना योगदान दिया। 1990 में जब आंदोलन ने गति पकड़ी, उससे पहले से ही भाजपा का देश की जनता को वादा था। हमने पालमपुर कार्यकारिणी के अंदर प्रस्ताव पारित करके कहा था कि राम मंदिर के निर्माण को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। यह देश की चेतना की पुनर्जागृति का आंदोलन है। जब हम घोषणा पत्र में कहते थे कि राम मंदिर बनाना हो, तीन तलाक हटाना हो, समान नागरिक संहिता लाना हो, अनुच्छेद 370 हटाना हो, तो कहा जाता था कि भाजपा ऐसे ही वादा करती है। लोग कहते थे कि हम वोट हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। जब हम वादा पूरा करते हैं तो उसका भी विरोध करते हैं।

अमित शाह ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जो बोलते हैं, वो करते हैं। हम 1986 से कह रहे थे कि वहां भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। कुछ लोग यहां प्रतिक्रिया दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की खंडपीठ के फैसले से आप वास्ता रखते हैं या नहीं? आप फैसले से कैसे कन्नी काट सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने भारत के पंथ निरपेक्ष चरित्र को उजागर किया है। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ, जब बहुसंख्यक समाज ने अपनी आस्था का निवर्हन करने के लिए इतनी लबी लड़ाई लड़ी हो और इंतजार किया हो। हमने राह देखी है, लड़ाई लड़ी है। हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। साथ में जुड़ जाओ, इसी में देश का भला है।

खेल
प्रमुख समाचार

इंग्लैंड के खिलाफ बाकी तीन टेस्ट के लिए टीम घोषित

नई दिल्ली। इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के बाकी बचे हुए मुकाबलों के लिए भारतीय टीम घोषित हो गई है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली सीरीज से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। वह पारिवारिक कारणों से शुरुआती दो टेस्ट में नहीं खेल पाए थे। बाकी बचे हुए मुकाबलों के लिए तेज गेंदबाज आकाश दीप सिंह को शामिल किया गया है। राजकोट में सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड की टीमें अब तक हुए दो टेस्ट में 1-1 की बराबरी पर हैं।

बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा, विराट कोहली व्यक्तिगत कारणों से सीरीज के बाकी बचे मैचों में चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। बोर्ड कोहली के फैसले का पूरा सम्मान और समर्थन करता है। टीम में रवींद्र जडेजा और केएल राहुल को चुना गया है। दोनों चोटिल हो गए थे और दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाए थे। चयन के बावजूद उनका खेलना तय नहीं है। बोर्ड ने बताया कि जडेजा और केएल राहुल की भागीदारी बीसीसीआई मेडिकल टीम से फिटनेस मंजूरी के अधीन है।

तीसरा टेस्ट 15 फरवरी को राजकोट में शुरू होगा। जबकि चौथा टेस्ट 23 फरवरी से रांची में खेला जाएगा। सीरीज का पांचवां और अंतिम टेस्ट सात मार्च से धर्मशाला में खेला जाएगा।

सीरीज के बाकी बचे तीन मुकाबलों के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), जसप्रीत बुमराह (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), केएस भरत (विकेटकीपर), आर अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, आकाश दीप।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए ईपीएफओ ने बढ़ाया इंटरेस्ट रेट

नईदिल्ली। पीएफ जमा करने वालों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने शनिवार को 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर मिलने वाली ब्याज दर में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। ईपीएफओ ने 2023-24 के लिए अब पीएफ जमा करने पर ब्याज दर 8.25 प्रतिशत तय कर दी गई है। बता दें कि पिछले तीन साल में यह सर्वाधिक है। ईपीएफओ ने मार्च 2023 में 2022-23 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को मामूली रूप से बढ़ाकर 8.15 प्रतिशत कर दिया था जो 2021-22 में 8.10 प्रतिशत थी। ईपीएफओ ने मार्च 2022 में 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को घटाकर 8.1 प्रतिशत कर दिया था, जो चार दशक में सबसे कम थी। वहीं, 2020-21 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.5 प्रतिशत थी। सीबीटी ने शनिवार को अपनी बैठक में 2023-24 के लिए ईपीएफ पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर प्रदान करने का निर्णय लिया है।

जिंदल स्टेनलेस का एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र से समझौता

नईदिल्ली। जिंदल स्टेनलेस ने मिसाइलों और उपग्रहों के प्रक्षेपण में उपयोग किए जाने वाले मूल्यवर्धित उत्पादों के विनिर्माण के लिए एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र विशाखापत्तनम के साथ एक समझौता किया है। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) ने शनिवार को बयान में कहा, यह सहयोग रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्य उद्योगों में उपकरणों के विकास के लिए जरूरी कलपूर्जों के विनिर्माण को बढ़ावा देगा। कंपनी ने कहा, भारत की रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विनिर्माण को मजबूत करने के लिए जेएसएल ने मिसाइल और उपग्रह प्रक्षेपण वाहन खंडों के लिए मूल्यवर्धित उत्पादों के विनिर्माण के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) प्रौद्योगिकी केंद्र, विशाखापत्तनम के साथ एक समझौता किया है। समझौते के तहत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रणालियों के लिए घटकों का विनिर्माण विशेष मिश्र धातुओं से किया जाएगा।

जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने निवेश के लिए ओडिशा सरकार के साथ एमओयू किया

नईदिल्ली। जेएसडब्ल्यू समूह ने ओडिशा में 40,000 करोड़ रुपये के निवेश से ईवी परियोजना स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जेएसडब्ल्यू समूह कटक जिले में एक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और कलपुर्जा विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगा। इसके अलावा जगतसिंहपुर जिले के पारादीप में एक तांबा स्मेल्टर और लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल के इन दोनों परियोजनाओं के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी देने के दो सप्ताह बाद समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि यह दिन औद्योगिक उत्कृष्टता और सतत वृद्धि की दिशा में राज्य की यात्रा में एक बड़ी छलांग का प्रतीक है।

ओमेक्स को दिसंबर तिमाही में 72 करोड़ रु. का नुकसान

नईदिल्ली। रियल्टी कंपनी ओमेक्स लि. को दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही में 71.77 करोड़ रुपये का एकीकृत घाटा हुआ। एक साल पहले की समान अवधि में इसका घाटा 109.11 करोड़ रुपये था। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि इस वित्तवर्ष की तीसरी तिमाही में परिचालन से होने वाली कुल आय बढ़कर 601.90 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 253.81 करोड़ रुपये थी। समीक्षाधीन अवधि में कुल खर्च भी पहले के 389.69 करोड़ रुपये से बढ़कर 683.66 करोड़ रुपये हो गया। ओमेक्स के निदेशक मंडल ने एक अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2029 तक यानी पांच साल की अवधि के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में मोहित गोयल की पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी। यह शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर है।

बजट में उत्कृष्ट वित्तीय संयम

अजीत रानाडे

बौराष्ट्रीय आम चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं, इसलिए इस बार का बजट लेखानुदान के रूप में पारित होना है। इसका अर्थ यह है कि इस अंतरिम बजट से किसी विशेष पहल की अपेक्षा नहीं थी और ऐसा किया भी नहीं जा सकता था। फिर भी ऐसे अवसर पर सत्तारूढ़ दल की ऐसी इच्छा का होना स्वाभाविक है कि वह कुछ वित्तीय ईंधन उपलब्ध कराए, जिससे चुनाव के समय अर्थव्यवस्था में गति आए। भारत के अपने चुनावी इतिहास में पहले ऐसे कुछ अंतरिम बजट प्रस्तुत किये जा चुके हैं। अमेरिका के एक राष्ट्रपति की प्रसिद्ध उक्ति है- इट्स द इकोनॉमी, स्टूपिड!' (यह अर्थव्यवस्था है, मूढ़!)। इस उक्ति का तात्पर्य यह है कि मतदाता हमेशा आर्थिक हित को दिमाग में रख कर मतदान करता है। यह बात भारतीय मतदाता पर भले ही पूरी तरह से लागू नहीं होती है, फिर भी चुनाव के समय सरकार की मंशा हमेशा ही वित्तीय विस्तार के लिए आवंटन की होती है।

एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत बजट प्रस्ताव के बारे में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें वित्तीय संयम प्रदर्शित किया गया है। इस बजट में जो खर्च प्रस्तावित किया गया है, वह वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 से लगभग छह प्रतिशत ही अधिक है। इस प्रस्तावित खर्च में राजस्व खर्च जैसा गैर पूंजी व्यय चालू वित्त वर्ष की तुलना में मुश्किल से 3.2 प्रतिशत अधिक है। यह तथाकथित 'गैर उत्पादक' या सामान्य खर्च है और इसकी बढ़ोतरी में बड़ी कटौती की गयी है। दो साल पहले राजस्व खर्च की वृद्धि दर आठ प्रतिशत रही थी। यहां तक कि बजट प्रस्ताव में पूंजी व्यय में आगामी वित्त वर्ष (2024-25) के लिए वृद्धि 17 प्रतिशत निर्धारित की गयी है,

जो बीते तीन साल से 31 प्रतिशत की दर से हो रही बढ़ोतरी से बहुत कम है। वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद को यह याद दिलाया कि वित्तीय घाटे के सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) के छह प्रतिशत रखने के लक्ष्य को चालू वित्त वर्ष में हासिल कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि इस लक्ष्य से बेहतर उपलब्धि रही है और वित्तीय घाटा 5.8 प्रतिशत के स्तर पर है। वित्तीय सादगी के लिए यह एक अच्छी खबर है, हालांकि वित्तीय घाटा अनुपात के कम रहने की सफलता में विभाजक यानी नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि दर का केवल 8.6 प्रतिशत रहना भी एक कारक है, जो अपेक्षा से कम रहा है। बजट में आगामी वित्त वर्ष के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य 5.1 प्रतिशत रखा गया, हालांकि विभाजक यानी नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि दर 10.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। मंत्री निर्मला सीतारमण का किसी वित्तीय जोखिम के चक्कर में नहीं पड़ने के इस तथ्य के दो अर्थ हो सकते हैं और दोनों अर्थ सही हो सकते हैं। पहली बात यह है कि सत्तारूढ़ दल को अपनी चुनावी संभावनाओं को बेहतर करने के लिए वित्तीय आकर्षण देने, विशेष रूप से बजट के माध्यम से, की आवश्यकता नहीं है। याद करें, डॉ मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली पहली यूपीए सरकार के समय लोकसभा चुनाव से लगभग डेढ़ साल पहले बड़े पैमाने पर कर्ज माफी की घोषणा की गयी थी। दूसरी बात यह है कि सरकार का अब मानना है कि आर्थिक वृद्धि वित्तीय रूप से हमेशा के लिए सरकारी खजाने से की जाने वाली पूंजी व्यय पर निर्भर नहीं रह सकती है। ऐसा होता रहा, तो राष्ट्रीय कर्ज पर इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि भारत का कर्ज जीडीपी के अनुपात में सौ प्रतिशत के स्तर पर जा सकता है। स्वाभाविक रूप से सरकार ने इस गंभीर भविष्यवाणी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कोरोना महामारी के दौर के बाद कर्ज का अनुपात असल में घट कर 88 से 82 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। सरकार ने यह भी कहा कि इस कर्ज का बड़ा हिस्सा घरेलू मुद्रा में है, न कि डॉलर में, लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि कर्ज अनुपात का 82 प्रतिशत रहना भी बहुत उच्च स्तर है और इससे निजी निवेश हतोत्साहित हो रहा है तथा ब्याज दरें बहुत अधिक बनी हुई हैं। इस कर्ज का ब्याज भरने में ही कर राजस्व का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा खर्च हो जाता है। इसलिए पूंजी का समेकन आवश्यक है। वित्तीय संयम की जरूरत है क्योंकि अधिक घाटा से ब्याज का बोझ बढ़ता है तथा मुद्रास्फीति बढ़ती है।

कही-सुनी

रवि भोई

दो महीने में साय सरकार की लंबी छलांग

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार को कामकाज संभाले 13 फ़रवरी को दो महीने हो जाएंगे। साय सरकार ने कोल, शराब,कस्टम मिलिंग और पीएससी घोटाले का पिटारा खोलकर प्रदेश की राजनीति को गरमा दी, तो वहीं किसानों को दो साल का बकाया बोनस, 18 लाख परिवारों को छत, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी और महतारी वंदन योजना का क्रियान्वयन कर मोदी गारंटी को पूरा करने के लिए कदमताल भी कर लिया। किसानों को 3100 की दर से धान की कीमत देने के लिए योजना बना ली है और बजट में राशि का प्रावधान कर लिया है। समर्थन मूल्य के अलावा अंतर की राशि 917 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को फरवरी महीने में मिल जाने की उम्मीद है। सरकार ने वादे पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाने के साथ बजट के माध्यम से आगे बढ़ने की दिशा भी तय की है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के अपने जीवन का पहला बजट सदन में पेश किया और बजट भाषण बिना टोका-टाकी के पढ़ा, यह बड़ी उपलब्धि रही।आकर्षक प्रस्तुति ने सदस्यों को बांधे रखा। बजट में भविष्य के सपने दिखाए गए हैं। पांच साल में सपने कैसे पूरे होते हैं, उसका इंतजार करना होगा।

भाजपा राज में कांग्रेस नेता की लाटरी

कहते हैं बस्तर इलाके में खनिज परिवहन के मामले में एक कांग्रेस नेता की लाटरी लग गई है। भूपेश बघेल की सरकार में धूप-छाँव के दिन बिताने वाले ये कांग्रेसी नेता अपने साउथ कनेक्शन से बस्तर में फिर से खनिज परिवहन का ठेका ले लिया है। कांग्रेस के राज में एक कांग्रेसी नेता ने ही उन्हें धंधे से बाहर कर दिया था। अब कांग्रेस नेता को परिवहन का ठेका मिलने पर भाजपा के भीतर भी बवाल हो गया है। कहते हैं बस्तर के एक विधायक ने अपने कुछ लोगों को परिवहन का ठेका दिलवाया था, पर दूसरे विधायक ने अपने पावर और संबंधों का इस्तेमाल कर एक कंपनी को काम दिलवा दिया। चर्चा है कि कंपनी पर दबाव बनाकर कांग्रेस नेता ने काम ले लिया। बताते हैं भाजपा के राज में कांग्रेस नेता को काम मिलने पर उठा बवंडर अब पार्टी हाईकमान तक पहुँचने वाला है।

आईजी सुंदरराज के सिर बस्तर का ताज बरकरार

लगता है आईजी सुंदरराज पी का बस्तर से चोली दामन का साथ हो चला है। डीआईजी और आईजी के तौर पर सुंदरराज पिछले सात साल से बस्तर की कमान संभाले हुए हैं। पिछले दिनों भाजपा की सरकार ने बड़ी संख्या में आईजी और एसपी के तबादले किए। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे बड़े रेंज के आईजी बदले, लेकिन बस्तर आईजी सुंदरराज की जगह नहीं हिली। 2003 बैच के आईपीएस सुंदरराज को रमन सरकार में बस्तर भेजा गया था। वे भूपेश बघेल के राज में भी बस्तर में रहे और विष्णुदेव साय के कार्यकाल में भी बस्तर का पट्टा बरकरार रहा। एक ही इलाके में लगातार सात साल तक कमान संभाले रहना भी, अपने आप में रिकार्ड है। सुंदरराज बस्तर के एसपी भी रह चुके हैं। बस्तर का इलाका नक्सल प्रभावित है और नक्सल इलाके में सुंदरराज मोर्चा संभाले हुए हैं। साय सरकार नक्सलियों के खात्मे के लिए आक्रामक कदम उठाना चाहती है,शायद इसी वजह से नक्सलियों के रग-रग से वाकिफ सुंदरराज को सरकार डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और अंगद के पाँव की तरह जमे रहने देना चाहती है।

सोनमणि बोरा की वापसी

सेन्ट्रल डेपुटेशन से आईएएस अफसरों की छत्तीसगढ़ वापसी के हो हल्ला के बीच 1999 बैच के अफसर सोनमणि बोरा को भारत सरकार ने राज्य वापसी की हरी झंडी दे दी है। बोरा के आने के बाद छत्तीसगढ़ में प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों में बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी निहारिका बारिक सिंह ही प्रमुख सचिव हैं। वैसे प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी गौरव द्विवेदी की वापसी की भी चर्चा है। गौरव द्विवेदी भूपेश राज में ही दिल्ली से लौटे थे। वे भूपेश सरकार में कुछ महीने तक मुख्यमंत्री के सचिव भी रहे। बाद में पटरी जमी नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री के सचिव के पद से हटाकर दूसरे विभागों में भेज दिया गया। इसके बाद वे फिर भारत सरकार में चले गए। गौरव द्विवेदी के आने की स्थिति में डॉ मनिंदर कौर द्विवेदी भी आ सकती हैं। वैसे मुकेश बंसल और अमित कटारिया के आने का भी हल्ला है। केंद्र सरकार के आईएएस अफसरों की वापसी की खबरों के बीच मंत्रालय में कई विभाग लिए अफसर अभी से सशंकित होने लगे हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले अफसरों को भी मातहत होने का भय सताने लगा है।

सीबीआई के लिए कब खुलेगा दरवाजा

वैसे विष्णुदेव साय की सरकार ने कामकाज संभालने के बाद ही कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ का दरवाजा सीबीआई के लिए खोलने का फैसला कर लिया था, लेकिन अभी तक चिट्ठी-पत्री दिल्ली गई नहीं है। कहते हैं लालफीताशाही के चक्कर में मामला अटका है। लोग चर्चा करने लगे हैं कि सीबीआई के लिए छत्तीसगढ़ का द्वार कब खुलेगा ? साय सरकार ने पीएससी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू में एफआईआर तो दर्ज करा दिया है,पर वादे के मुताबिक़ सीबीआई जांच का लोगों को इंतजार है। पीएससी घोटाला के अलावा कोल लेवी,कस्टम मिलिंग, शराब घोटाला भी सीबीआई जांच के इंतजार में है। रमन राज तक छत्तीसगढ़ में सीबीआई की इंट्री थी। भूपेश बघेल के शासनकाल में राज्य में सीबीआई को प्रतिबंधित कर दिया गया। विष्णुदेव की सरकार को प्रतिबंध हटाकर सीबीआई के सुपुर्द मामले करने हैं।

भाजपा पदाधिकारी की नजर राज्यसभा सीट पर

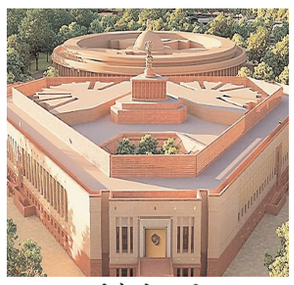

कहते हैं प्रदेश के एक भाजपा पदाधिकारी की नजर अप्रैल में खाली होने वाली राज्यसभा की सीट पर है। इसके लिए वे जुगाड़-तुगाड में लगे हैं और अपने समाज का भी सहारा ले रहे हैं। कुछ लोग राज्यसभा के लिए रामप्रताप सिंह का नाम भी आगे कर रहे हैं, वहीं बस्तर में जनसंघ के जमाने से लगे सामान्य वर्ग के नेता भी दावा कर रहे हैं। कहा जा रहा है राज्यसभा के उम्मीदवार का नाम तो दिल्ली से ही तय होगा। संभावना है कि राज्यसभा के लिए भाजपा हाईकमान 19 फ़रवरी के बाद प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो जाएगा। इसके लिए 27 फ़रवरी को मतदान होना है। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर राज्यसभा की सीट भाजपा के खाते में जाना तय है।

चुनाव आयोग की आँखों में चढ़े शलभ सिन्हा जगदलपुर एसपी

दुर्ग के एसपी रहते चुनाव आयोग के निशाने पर आए 2014 बैच के आईपीएस शलभ सिन्हा को भाजपा की सरकार ने जगदलपुर जैसे नक्सल प्रभावित और बड़े जिले की कमान सौंपी है। विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान एक राजनीतिक पार्टी ने आईपीएस शलभ सिन्हा की शिकायत की थी। शिकायत पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने शलभ सिन्हा को दुर्ग के एसपी पद से हटा दिया था, उनकी जगह रामगोपाल गर्ग को दुर्ग का एसपी बनाया गया था। अब चुनाव निपटने और नई सरकार की पहली पुलिस सर्जरी में शलभ सिन्हा एआईजी पुलिस मुख्यालय से जगदलपुर पहुंच गए। शलभ सिन्हा के साथ चुनाव आयोग द्वारा हटाए गए दूसरे पुलिस अफसरों का अभी पुनर्वास नहीं हुआ है।

सदानंद कुमार दूसरी बार बलौदाबाजार के एसपी

2010 बैच के आईपीएस सदानंद कुमार दूसरी बार बलौदाबाजार -भाटापारा जिले के एसपी बनाए गए हैं। सदानंद कुमार की एसपी के तौर पर पहली पोस्टिंग बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में ही हुई थी। सदानंद कुमार अंबिकापुर, बलरामपुर, बालोद, नारायणपुर और रायगढ़ के एसपी रह चुके हैं। 2009 बैच के आईपीएस अमित कांबले के बाद सदानंद कुमार दूसरी बार एक ही जिले में एसपी के रूप में पहुंचे हैं। अमित कांबले 2015-16 में गरियाबंद के एसपी थे। अक्टूबर 2022 से फिर गरियाबंद के एसपी हैं।

कांग्रेस नेता के रिश्तेदार की जुगत

चर्चा है कि भूपेश बघेल के शासनकाल में एक कांग्रेस नेता जिस निगम के अध्यक्ष थे, अब उसी निगम का एमडी उनके रिश्तेदार को बनाया गया है। एमडी बनाए गए अफसर न तो आईएएस हैं और न ही आईएफएस और न ही राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर। केंद्र सरकार के डूबत वाली संस्था से जुड़ी सेवा के अफसर छत्तीसगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर हैं। पिछली सरकार में कर्मचारी नेताओं की निगाह पर चढ़े अफसर को फील्ड से मंत्रालय में लाया गया था। विष्णुदेव साय की सरकार में ये मंत्रालय से निगम के कार्यकारी बनने में सफल रहे। ये जिस सेवा के हैं, उस सेवा के दो अफसर ईडी के फेर में आ चुके हैं।

टंकराम वर्मा के तीन लाल

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। शिक्षक रहने के साथ विधायक और मंत्री के पीए रहकर राजनीति और प्रशासन को करीब से देखा है। इसके बावजूद मंत्री की हैसियत से अब जब वे बलौदाबाजार जाते हैं, लोग उन्हें घेर लेते हैं और ज्ञान की बातें समझाते हैं। यहां तक उन्हें राजनीति के गुर सिखाते हैं। इसमें वे लोग शामिल हैं जो कांग्रेस या बसपा में रहते और न ही निर्दलीय चुनाव जीत सके हैं। यह अलग बात है कि अब वे भाजपा के कर्णधार बन गए हैं। कहते हैं कि मंत्री जी जब भी बलौदाबाजार जाते हैं तीनों लोग पूरे समय घेरे रहते हैं। इस कारण तीनों की चर्चा टंकराम वर्मा के लाल के रूप में होने लगी है।

छग में खुलेगी 'मोहब्बत की दुकान': पूर्व मुख्यमंत्री बघेल

रायपुर. भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है. यात्रा को लेकर उन्होंने कहा, राहुल गांधी कल से यात्रा शुरू करेंगे. लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है. पांच न्याय को लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं. 13 फरवरी को अंबिकापुर में सभा होगी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ सकते हैं. राहुल गांधी की यात्रा

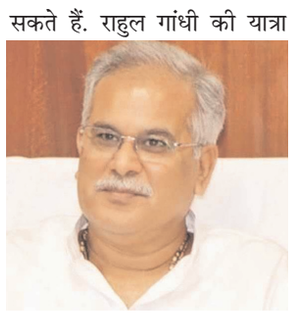

राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन इसका फायदा लोकसभा में मिलेगा. लोकसभा के पहले पूरे देश में गृहमंत्री ने सीएए लागू करने की बात की है, जिसको लेकर भूपेश बघेल ने तंज कसा है.

उनका कहना है कि इसका नुकसान छत्तीसगढ़ को होगा. यहां तो आपको सर्टिफिकेट से साबित करना पड़ेगा कि आप भारतीय हैं या नहीं. असम और अन्य जगह लोगों ने सर्टिफिकेट बना दिए, लेकिन गरीब आदिवासी कैसे साबित करेंगे ? इतना ही नहीं मुख्यमंत्री साय की कानून व्यवस्था की बैठक और बयान पर भी भूपेश बघेल ने पलटवार किया है. भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा, सही कह रहे हैं कि अपराध में कमी आनी चाहिए. लेकिन दूसरों को अंदर करें और अपनों को छोड़ दें यह नहीं होना चाहिए.

'गुंडे-बदमाश जान ले, हवा बदल चुकी है'- मुख्यमंत्री साय

रायपुर. भाजपा नेता असीम राय हत्याकांड के आरोपी कांग्रेस नेता सोमेन मंडल के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. सोमेन मंडल के अवैध मेडिकल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया है. जिसका वीडियो मुख्यमंत्री साय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म (ङ्क) पर शेयर किया है. वीडियो और पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री ने गुंडे-बदमाशों को चेतावनी दी है. मुख्यमंत्री साय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अपराधी, माफिया व गुंडे-बदमाश जान ले, अब हवा बदल चुकी है. ये सरकार अपराधियों को संरक्षण नहीं 'सजा' देगी.

न रजिस्ट्री हो रही, और न ही मिल रहा अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्री का नया सॉफ्टवेयर बना परेशानी का सबब

रायपुर। रायपुर में शुरू हुआ जमीन रजिस्ट्री का नया सिस्टम न केवल क्रेता-विक्रेता बल्कि अधिवक्ताओं के लिए भी परेशानी का सबब बन गया है. इन परेशानियों से अधिकारियों को अवगत कराने के लिए कलेक्टर परिसर स्थित रेड क्रॉस भवन में अधिवक्ता जुटे. रजिस्ट्रार, एनआईसी के अधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया. अधिवक्ता संस्कार जैन ने बताया कि रजिस्ट्री ऑफिस में एक नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी खामियां हैं. डॉक्यूमेंट अपडेट होने में समस्या हो रही है. डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके मिलने में प्रॉब्लम हो रही है. कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है. कोई मल्टी स्पेशल स्टोरी है, उसका बिल्डिंग नहीं आ रही है. ऐसे बहुत सारी टेक्निकल समस्या है.अधिवक्ता ने बताया कि इसके अलावा बहुत से गांव नहीं जोड़े गए है.

प्रमुख समाचार
छत्तीसगढ़/राजधानी

मोदी की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्री द्वारा जारी किया गया श्वेत पत्र सच्चाई का वो आईना है जिससे कांग्रेस पार्टी के एक परिवार ने देश के सामने नहीं आने दिया था। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र इस बात की साक्षी है कि 2004 और 2014 के बीच की कांग्रेस की यूपीए सरकार की अवधि की तुलना में 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार हुआ। यूपीए ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, बल्कि यूं कहिये कि देश को लूटा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार से एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था विरासत में मिलने के बावजूद यूपीए ने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे गैर-निष्पादित अर्थव्यवस्था में बदल दिया, इसकी जानकारी हमें इस श्वेत पत्र में मिलती है। कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान देश की जो बदहाल आर्थिक स्थिति थी, उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं उस वक्त सरकार का नेतृत्व कर रहे लोग भी थे। पीएम से लेकर सुपर पीएम तक।

देश भर में ऑन लाईन ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 14 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर. प्रार्थिया निवासी संजय नगर, रायपुर ने थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह बिजली विभाग से डिप्टी जनरल मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुई है. राम किशन वर्मा तथा पुनीत जोशी नामक व्यक्तियों ने वर्ष 2016 से लगातार प्रार्थिया के मोबाईल फोन में अलग ङ्क अलग मोबाईल नंबरों से फोन कर ठगी की घटना को अंजाम दिये है. जिसमें प्रार्थिया को उसके पुराना बीमा पॉलिसी के आधार पर नई बीमा पॉलिसी दिलाने एवं सेवानिवृत्त के समय सभी पॉलिसी का पैसा एक साथ प्रार्थिया को मिलने से उसे अच्छा फायदा होने का झांसा दिया गया. तत्पश्चात् राम किशन वर्मा तथा पुनीत जोशी (काल्पनिक नाम) के नाम से दो व्यक्तियों द्वारा प्रार्थिया की पुरानी बीमा पॉलिसी को आधार बनाकर फर्जी कागजात तैयार किया गया तथा प्रार्थिया को मोबाईल फोन के माध्यम से बारम्बार फोन करके अपने झांसे में लेकर दिनांक 12.01.2017 से अलग-अलग तिथियों में व विभिन्न किश्तों में प्रार्थिया से करीबन 70 लाख रूपये प्रार्थिया को पैसे जमा करने हेतु कुल 05 बैंक खाता उपलब्ध कराकर उससे उक्त राशि जमा कराया गया.

बच्चों का भविष्य है, खिलौना नहीं- नौकरी नहीं 1 साल से मौज काट रहा शिक्षक

लोरमी. मुंगेली जिले के लोरमी तहसील में इन दिनों शिक्षकों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है. वहीं शासकीय मिडिल स्कूल लालपुर थाना में 220 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जहां हिंदी के शिक्षक की मनमर्जी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है. जिले के लालपुर थाना स्थित मिडिल स्कूल में पदस्थ शासकीय शिक्षक संजय कुमार कश्यप जो 14 माह से स्कूल से गायब हैं. वहीं इनके खिलाफ स्कूल प्रबंधन ने कई दफा जिला शिक्षाधिकारी के दफ्तर में इसकी लिखित सूचना भी दिया गया. इसके बावजूद अब तक शिक्षा विभाग के अधिकारी बेसुध हैं.नदारद शिक्षक को लेकर प्रभारी प्राचार्य एम आर बर्मन ने बताया कि 14 माह से अनुपस्थित शिक्षक का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है. साथ ही उनके खिलाफ डीईओ कार्यालय में पत्राचार किया गया है, जिसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इसके साथ ही मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक संतप्रसाद पात्रे ने भी बताया कि 14 माह से शिक्षक संजय कुमार कश्यप नदारद हैं, जिनके द्वारा एक आवेदन जाने के समय दिया गया था. उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है. इसकी जानकारी पत्र के माध्यम से कई बार विभागीय अधिकारियों को दी गई. जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लिहाजा उनके खिलाफ शासन के नियम के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए.

नगर निगम सामान्य सभा की बैठक 21 को होगी, महापौर ढेबर पेश करेंगे बजट

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के सचिवालय द्वारा निगम सभापति श्री प्रमोद दुबे के आदेशानुसार नगर पालिक निगम मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन के चतुर्थ तल पर सामान्य सभा सभागार में सामान्य सभा की बैठक 21 फरवरी को प्रातः 11 बजे आहुत की गयी है। महापौर एजाज ढेबर वित्त वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट पेश करेंगे। सामान्य सभा की बैठक के बाद प्रश्नकाल होगा जिसमें पार्षदों द्वारा पूछे गये प्रश्नों एवं उनके जवाब की कार्यवाही होगी. प्रश्नकाल हेतु एक घण्टे की अवधि नियमानुसार निर्धारित है. प्रश्नकाल उपरांत नगर निगम रायपुर के वार्षिक बजट वित्त वर्ष 2024-25 की प्रस्तुति होगी. नगर निगम के महापौर श्री एजाज ढेबर वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट पर महापौर का अभिभाषण निगम सामान्य सभा की बैठक में प्रस्तुत करेंगे. बजट वित्त वर्ष 2024-25 सहित नियमानुसार नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक में लिये गये संकल्पों के अनुसार निर्धारित एजेंड़ों पर नियमानुसार प्रक्रिया के अन्तर्गत चर्चा एवं विचार - विमर्श नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में किया जायेगा

उमंग-2024 के विजेताओं को मिले पुरस्कार

रायपुर. अग्रसेन महाविद्यालय पुरानी बस्ती में आज वार्षिक उत्सव उमंग-2023 सहित वर्ष भर में हुई गतिविधियों के विजेताओं को सम्मानित किया गया. इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा आमंत्रित थे. वहीं ठाकुर रामचन्द्रजी स्वामी जैतूसाव मठ सार्वजानिक न्यास (रायपुर) के सचिव श्री महेंद्र अग्रवाल कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे. इस अवसर पर शिक्षाविद डॉ रविन्द्र अग्रवाल एवं डॉ मधुलिका अग्रवाल, वरिष्ठ समाजसेवी उमेश अग्रवाल, कृषि विज्ञानी सुनील अग्रवाल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे. इन सभी अतिथियों के हाथों विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किये गए मुख्य अतिथि श्री शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि युवावस्था में अकादमिक शिक्षा के साथ ही संस्कार-शिक्षा, खेल-कूद और अन्य गतिविधियों को महत्व देने से विद्यार्थी का सम्पूर्ण विकास होता है. श्री शर्मा ने विभिन्न स्पर्धाओं के विजेता विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामना दी. वर्ष भर अलग-अलग स्पर्धाओं में परिश्रम करने के बाद पुरस्कार पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे. कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री महेंद्र अग्रवाल ने कहा कि इस संस्थान में पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों को भी पर्याप्त महत्व दिया जाता है. इसीलिए यहाँ के छात्र अनेक विधाओं में सफलता प्राप्त करते हैं, जो कि अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा का विषय है.

समाज के युवाओं से नशापान से दूर रहने की अपील

शिक्षा को बढ़ावा देकर समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है- साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखण्ड के ग्राम मुडाटोली में आयोजित अखिल भारतीय कंवर समाज के अंचल स्तरीय वार्षिक सम्मेलन सह मिलन समारोह 2024 में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही किसी समाज के विकास का मूलमंत्र है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा सिर्फ नौकरी तक ही सीमित नहीं है, बेहतर जीवनयापन के साथ समाज सेवा, राजनीति, व्यापार के क्षेत्र में जाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण साधन है। आज सरकार द्वारा बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के बेहतर प्रबंध किए गए हैं। सभी अभिभावकों का दायित्व है कि वे अपने बच्चों को शिक्षित करें। मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं में बढ़ते नशा के प्रकोप को रोकने और युवाओं को सही दिशा में ले जाने की अपील की। सम्मेलन में समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री का गज माला के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने

आपके कँवर समाज और आदिवासी समाज पर भरोसा जताते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। यह समाज के लोगों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि समाज का आशीर्वाद उन पर बना रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि इस तरह के सम्मेलन के माध्यम से समाज कैसे मजबूत हो इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी सरकार बने दो माह ही हुए हैं। इस दौरान 18 लाख से अधिक लोगों के पीएम आवास की स्वीकृति, दो वर्ष के धान के बकाया बोनस की राशि किसानों के खाते में अंतरित की गई है। उन्होंने इस साल धान की बम्फर खरीदी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना से अगले माह से विवाहित महिलाओं के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप सभी पात्र महिलाएं अपना आवेदन जरूर भरें। मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रति मानक बोरा में वृद्धि करते हुए 5500 रुपये करने और संग्राहकों को बोनस, चरणपादुका का वितरण, परिवार के बच्चों को छात्रवृत्ति सहित अन्य लाभ देने की बात कही।

प्रदेश में महतारी वंदन योजना शुरू होने से प्रदेश की माताएं बहुत खुश हैः उप मुख्यमंत्री शर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज कबीरधाम जिले के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान सहसपुर लोहारा जनपद पंचायत के ग्राम खजरीकला और ग्राम बाम्बी, बसिंझोरी और लखनपुर में आयोजित मड़ाई मेला में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं और माताओ से हमने वादा किया था कि प्रदेश में नई सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना शुरू की जाएगी। श्री साय सरकार ने उस गारंटी को पूरा किया। प्रदेश में महतारी वंदन योजना शुरू हो गई है। योजना शुरू होने से प्रदेश की माताएं बहुत खुश है। अब जल्द ही महतारी वंदन योजना के तहत हर माह पात्र हितग्राहियों को एक हजार रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। राज्य के बजट में इसके लिए प्रावधान

किया है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश की महिलाए, माताएं, शक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा को आगे बढाते हुए प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में सिर्फ महिलाओ-माताओ के लिए महतारी सदन बनाया जाएगा। प्रदेश विष्णुदेव की सरकार इस दिशा में जल्द की फैसला करेगी। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्राम खजरिकला में पंचायत में निर्माण कार्य के लिए 7 लाख रुपए, ग्राम बांमी में सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रुपए, आश्रित ग्राम में बनखैरा में मंच निर्माण के लिए 2 लाख रुपए और लखनपुर में सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.